जून, 2022, वर्ष : 43 अंक : 06 www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश

तिब्बत पर आठवें विश्व सांसद सम्मेलन मे सिक्योंग पेन्पा छेरिंग, अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर खेंपो सोनम तेनफेल।

मूल्य :10 रु , वार्षिक : 100 रु

जून, 2022, वर्ष : 43 अंक : 06

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

निर्वासित तिब्बती सरकार द्वारा नीति संस्थान के पूर्व निदेशक श्री थुबटेन सम्फेल के निधन पर शोक सभा।

प्रधान संपादक
जमयंग दोरजी

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
तेनजिन पलजोर , तेनजिन जोरदेन

वितरण प्रबंधक
छोन्यी छेरिंग

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

समाचार -

- तिब्बत पर आठवें विश्व सांसद सम्मेलन को परम पावन दलाई लामा का संदेश
- असम में राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग
- कैद तिब्बती भिक्षु को परिजनों से मिलने की अनुमति नहीं मिली, उन्हें जेल में 'देशभक्ति शिक्षा' और 'कठोर श्रम' के लिए भेजा
- हाल की सजाओं ने तिब्बती बुद्धिजीवियों और लेखकों पर चीन के निरंतर दमन को साबित कर दिया
- युवा तिब्बती लोडो की मनमानी गिरफ्तारी के ६ महीने बाद भी उनका परिवार अंधेरे में
- चीनी अधिकारियों ने निर्वासित तिब्बतियों से संपर्क करने के आरोप में तिब्बती छात्र को तीन साल की सजा सुनाई
- परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म के बारे में निर्णय लेने का अधिकार स्वयं परम पावन और तिब्बतियों के पास:सिक्योंग
- सिक्योंग ने वाशिंगटन में तिब्बत के प्रतिनिधि कार्यालयों की बैठक की अध्यक्षता की
- तिब्बत के लिए सांसदों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के पुनरुद्धार के साथ तिब्बत पर आठवें विश्व सांसद सम्मेलन का समापन
- तिब्बत पर आठवें विश्व सांसद सम्मेलन की घोषणा
- प्रो. समदोंग रिनपोछे ने तिब्बत पर लिखी 'तुम्हारा नाम क्या है-तिब्बत' शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया

समाचार -

- 'चीन पर कांग्रेस के कार्यकारी आयोग' ने तिब्बत मुद्दे को लेकर सुनवाई की
- ई-गवर्नेंस के लिए सीटीए प्रतिनिधिमंडल का एस्टोनिया अध्ययन दौरा
- लोकसभा के सांसद तपीर गाओ ने अरुणाचल प्रदेश में चोफेलिंग तिब्बती सेटलमेंट का दौरा किया
- मुझे बोलने के परिणाम का पछतावा नहीं है : एनेस कांटर फ्रीडम
- प्रतिनिधि डॉ. आर्य ने टोक्यो में तियानमेन मेमोरियल कार्यक्रम में भाग लिया
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का५०वां सत्र: ४७सदस्य देशतिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर 'गंभीर रूप से चिंतित'
- प्रतिनिधि डॉ. आर्य ने जापानी संसद के सम्मेलन कक्ष में प्रेस बैठक में भाग लिया
- दलाई लामा राष्ट्र के रूप में तिब्बत के अंतिम प्रतीक हैं
- शोक संदेश : डीआईआईआर ने श्री थुबटेन सम्फेल के निधन पर शोक व्यक्त किया

मुद्रक एवं प्रकाशक जमयांग दोरजी द्वारा प्रेम गुलाटी , डोली ऑफसेट प्रिंटर्स , डी -१५२ , एफ. एफ. सी. ओखला , नई दिल्ली -११००२० से मुद्रीत

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट www.indiatibet.net Email: indiatibet7@gmail.com

थुबटेन सम्फेल का संक्षिप्त विवरण

विश्व संसदीय सम्मेलन में तिब्बत-चीन वार्ता की अपील

वाषिंगटन में सम्पन्न तिब्बत पर आठवं विश्वसंसदीय सम्मेलन (22 एवं 23 जून,2022) की घोशणा से स्पश्ट है कि चीन सरकार पूरी तरह सेब बेनकाब हो चुकी है। अन्तरराश्ट्रीय कानून, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा मानवता की घोरउपेक्षा कर चीन ने स्वतंत्र तिब्बत पर 1959 में अवैध कब्जा किया था। उसन अफवाह फैर्लाइ कि तिब्बत उसी का अभिन्न अंग था। फिर उसने भ्रम फैलाया। कि उसने तिब्बत को स्वायत्तता दी है। स्वायत्तता के नाम पर तिब्बत के भौगोलिक क्षेत्र को चीनी भू-भाग में मिलाते हुए उसने उसका शड्यंत्रपूर्वक चीनीकरण जारी रखा। यह साम्राज्यवादी नीति आज भी जारी है। इसी औपनिवेषिक चीनी नीति की कटु आलोचना करते हुए सम्मेलन में शामिल 28 देषों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने चीन सरकार से मांग की कि वह तिब्बती धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा तथा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ पुनः वार्ता प्रारम्भ करे।

चीन सरकार वार्ता की प्रक्रिया को उलझाती और टालती जा रही है। उसे आषंका है कि पुनः वार्ता प्रारम्भ हाने पर उसे तिब्बत को "वास्तविक स्वायत्तता" देनी होगी। प्रतिरक्षा तथा राश्ट्रीयता संबंधीविशय चीन के पास ही रहेंगे। सभी विशय जैसे-शिक्षा, कृशि आदि तिब्बतियों को मिल जायेंगे। इस से चीन की भौगोलिक एकता-अखंडता सुरक्षित रहेगी तथा तिब्बतियों को भी स्वयशासन का अधिकार मिल जायेगा। यही है तिब्बत समस्या के समाधान का "मध्यमार्ग" ।

लगभग सभी तिब्बत समर्थक तिब्बत की पूर्ण आजादी के पक्ष में हैं फिर भी वे मध्यमार्ग पर आधारित तिब्बतियों की "वास्तविक स्वायत्तता" की मांग का समर्थन कर रहे हैं। दलाई लामा समेत तिब्बती नेतृत्व तिब्बत में जारी चीनी करण के विरुद्ध है। तिब्बती पहचान खोने का अर्थ है-स्वाभिमानषून्य होना। चीन तिब्बत में विकास के नाम पर तिब्बती पहचान मिटाने में लगा है। यही कारण है कि तिब्बती ने तृत्वपूर्ण आजादी की मांग को छोड़कर वास्तविक स्वायत्तता लेने को तैयार है। विष्व संसदीय सम्मेलन में तिब्बतियों की इस मांग का जोरदार समर्थन प्रमाणित करता है कि विष्व जनमत चीनी विस्तारवादी नीति के विरुद्ध है।

सम्मेलनमें शामिल प्रतिनिधियों का दृढ़ निष्चय है किवे अपने देषों में स्पश्ट तिब्बत अधिनियम का निर्माण करायेंगे, जैसाकि अमरीका में है। इस अधिनियम में चीन से कहा गया है कि वह दलाई लामा के पुन र्जन्म अर्थात् अवतार की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करे। इस प्रक्रिया के पालन तथा निर्णय का अधिकार सिर्फ तिब्बती धर्मगुरुओं को है। इसमें धर्मविरोधी वामपंथी चीन सरकार का हस्तक्षेप अस्वीकार्य होगा। सम्मेलन की घोशणा में तिब्बत में मानवाधिकार, पर्यावरण, संस्कृति, धर्म आदि की स्थिति को चिंताजनक मानते हुए चीन सरकार से सुधार की अपील की गई।

जून माह में ही अपने अमरीका प्रवास में निर्वासित तिब्बती सरकार के सिक्योंग पेंपा त्सेरिंग ने तिब्बत की 16 वीं कसाग की दोनों प्रतिबद्धताओं को प्रमुखता से उजागर किया। कसाग की पहली प्रतिबद्धता है मध्यमार्ग से तिब्बती संकट का समाधान। दूसरी प्रतिबद्धता है तिब्बती समुदाय का कल्याण। तिब्बती तिब्बत के साथ भारत सहित कई देषों में हैं। सभी तिब्बतियों का कल्याण सुनिष्चित करना तथा उसके लिए योजना-निर्माण एवं क्रियान्वयन विभिन्न देशो की जनता और उनकी सरकारों के सहयोग से ही संभव है। तिब्बती बस्तियों में स्थानीय प्रशासन का सहयोग एवं समर्थन मिलता रहे इसके लिये तिब्बतन एडवोकेसी कैंपेन चलाया जा रहा है। विभिन्न देषों में सुव्यवस्थित रूप से संचालित तिब्बतन एडवोकेसी कैंपेन के परिणामस्वरूप तिब्बती संघ र्शकी सफलता के लिये नई राजनीतिकरण नीति विश्व स्तर पर आकार ले रही है। चीन सरकार की धमकियों तथा विरोधों के बावजूद तिब्बत के पक्ष में ऐसी एकजुटता से चीन पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है।

तिब्बती और तिब्बत समर्थक चाहते हैं कि बौद्ध दर्शन में निहित मानवीय मूल्यों अर्थात् लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार चीन में भी हो। शांति, अहिंसा, करुणा तथ सद्भाव चीन के भोगवादी विस्तारवाद पर अंकुष लगायेंगे। इस से चीन में जारी अनियंत्रित भोगवाद से जनता को छुटकारा मिलेगा। दलाई लामा अपने आध्यात्मिक प्रवचनों में इन्ही आदर्शो-मूल्यों को प्रकाशित-प्रचारित-प्रसारित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिलेमें धर्मशाला स्थित अपने निवास एवं मंदिर से वे इसी की प्रार्थना करते है। वे सबका कल्याण चाहते हैं। चीनियों के लिये भी उनके हृदय में करुणा है। उनके अनुसार प्रचीन नालंदा परंपरा यही है। धर्म विरोधी, अधार्मिक या विधर्मी के लिये भी मानवीय मूल्य जरुरी हैं।

दलाई लामा के दीर्घ जीवन हेतु तिब्बती एवं तिब्बत समर्थक व्यापक स्तर पर पूजा एवं प्रार्थना करते हैं। उन्हें प्रोत्साहित करते हुए 86 वर्शीय दलाई लामा ने आश्वस्त किया है कि 20-30 साल वे अभी और जीवित रहें गे। आश्चर्य है कि दलाई लामा को चीन सरकार अपना शत्रु समझती है। उसकी नजर में वे विघटनकारी और आतंककारी हैं। स्वतंत्र तिब्बत के राजप्रमुख रहे दलाई लामा को, जोकि शांति-करुणा के प्रती कहैं, चीन सरकार भले बुरा समझे लेकिन सच्चाई से विश्व समुदाय परिचित है।

भारत मे दलाई लामा का योगदान प्रशसनीय है। सभी भारतीय इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञ हैं। उनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद से प्राचीन भारतीय नालंदा संस्कृति को विष्व स्तर पर नया जीवन मिला है। इसी संस्कृति के बल पर भारत विशवागुरु कहलाता था। तथाकथित "हिन्दी चीनी भाई-भाई" और" पंचशील" के माया जाल से निकल कर शक्तिशाली भारतका निर्माण हमारा लक्ष्य रहे।

प्रो. श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय, तिजारा (राजस्थान)
मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

• तिब्बत पर आठवें विश्व सांसद सम्मेलन को परम पावन दलाई लामा का संदेश

tibet.net, २३जून २०२२

धर्मशाला। परम पावन दलाई लामा ने तिब्बत को लेकर आठवें विश्वसांसद सम्मेलन का एक संक्षिप्त वीडियो संदेश देकर उद्घाटन किया।

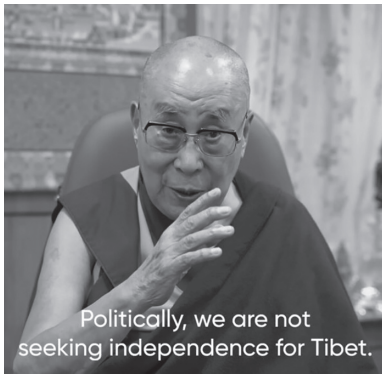

तिब्बत पर आठवें विश्व सांसद सम्मेलन पर सन्देश देते परम पावन दलाई लामा।

परम पावन ने कहा, 'आज तिब्बती मुद्दे के समर्थक विभिन्न समूहों के लोग तिब्बत पर चर्चा करने के लिए वाशिंगटन डीसी में एकत्रित हो रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक ओर तिब्बत का मुद्दा सच्चाई पर आधारित है तो दूसरी ओर इसमें करुणा और आंतरिक शांति को विकसित करने की दृष्टि से मन के कार्यों की समझ शामिल है। इसलिए यह केवल राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि विश्वास और तर्क पर आधारित मन की शांति को पाने से भी संबंधित है।'

आठवीं शताब्दी में तिब्बत में महान आचार्य शांतरक्षित द्वारा भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रचारित करने की घटना को याद करते हुए परम पावन ने कहा, 'हमने उस संस्कृति को इस हद तक आत्मसात कर लिया है कि तिब्बत के छोटे बच्चे भी करुणा व्यक्त करते हुए कहते हैं, 'कीड़े को भी मत मारना।' हम बचपन से ही करुणा का भाव रखने वाने वाले लोग हैं। लेकिन यह अच्छी प्रथा केवल तिब्बतियों तक ही सीमित नहीं हो सकती है। हम दूसरों को प्रेम और करुणा के महत्व से अवगत करा सकते हैं। इसकी साधना में पारंगत तिब्बती ऐसा करते रहे हैं और उन्हें उस लक्ष्य में योगदान देना जारी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा करने का अवसर है।'

परम पावन ने आगे कहा, 'ये मुद्दे केवल तिब्बत से संबंधित नहीं हैं। पूरी दुनिया स्वाभाविक रूप से शांति चाहती है और शांति नेक दिल में निहित है। यह उन सभी मानवों के लिए एक सच्चाई है। मनुष्यों की माताएं उनके जन्म के समय से ही प्यार और स्नेह से उनकी देखभाल करती हैं। हम सभी इसलिए जीवित हैं, क्योंकि हमारी माताएं हमें प्यार और अपने स्तन के दूध से पालती हैं। दुनिया के हर इंसान की तरह ही तिब्बती भी इंसान हैं जो अपनी मां के प्यार और स्नेह से पलते-बढ़ते हैं।

शांति प्राप्त करने में प्रेम और करुणा की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए परम पावन दलाई लामा ने बताया कि पश्चिम से आई आधुनिक शिक्षा की प्रणाली मुख्य रूप से भौतिकवाद के इर्द-गिर्द चक्कर काटती है। यह मन और भावनाओं की गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं है, न ही यह मन की शांति प्राप्त करने का कोई साधन बताती है। हालांकि, आजपश्चिम के विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों और न्यूरो साइंटिस्टों के बीच प्रेम और करुणा की भावना विकसित करने के लिए हमारी परंपरा के बारे में जानने की रुचि बढ़ रही है। मेरा मानना है कि हम अपने मन को समझने के परंपरागत ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर प्रेम और करुणा को विकसित करने और मन की शांति प्राप्त करने की विधि को समझा सकते हैं।' परम पावन ने आगे कहा 'हम सभी खुश रहना चाहते हैं और इसके लिए एक अच्छा दिल का होना अति आवश्यक है। मनुष्य के रूप में हम सभी सुख और दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन केवल खाने के लिए पर्याप्त होने और कुछ अल्पकालिक मनोरंजन का आनंद लेने से हमें स्थायी खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है। वास्तव में प्रसन्नता हमारे चारों ओर शांतिपूर्ण वातावरण उत्पन्न करती है। चाहे हम कहीं भी हों, है न?'

परम पावन ने तिब्बती संस्कृति में गहराई से निहित प्रेम और करुणा के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, 'तिब्बती संस्कृति चित्त और भावनाओं की गतिविधि से संबंधित है। यह केवल देवताओं या नागों का आह्वान करने का अनुष्ठान भर नहीं है। यहां तक कि जो इस संस्कृति में विश्वास नहीं करते हैं लेकिन अगर उनका दिल उदार है तो वे भी इससे खुश होंगे।है कि नहीं? प्रमुख कारक प्रेम और करुणा है। निर्वासन में रहते हुए कई लोगों के सहयोग से हमने अपनी क्षमता के अनुसार अपनी विरासत को सुरक्षित रखने का कार्य किया है और इसका कुछ फल भी मिला है। जहां तक मेरी बात है, मैं इस संस्कृति में पला-बढ़ा हूं।इसलिए मैं जहां भी जाता हूं, लोगों से प्यार और करुणा के बारे में बात करता हूं। राजनीतिक रूप से हम तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं। मैंने वर्षों पहले इसे स्पष्ट कर दिया था। हमारी संस्कृति और भाषा को संरक्षित और सुरक्षित करने का महत्व सबसे अधिक चिंता का विषय है। आज वास्तविकता यह है कि चीन में भी बौद्ध धर्म में रुचि लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसी परिस्थितियों मेंयदि हम सौहार्दता और नैतिकता की अपनी तिब्बती संस्कृति को पुनर्जीवित और विस्तारित करते हैं, तो यह न केवल तिब्बतियों, बल्कि बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि वाले अन्य लोगों जैसे मंगोलियाई और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन के लोगों को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। हम बौद्ध धर्म का प्रचार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भले ही आप धार्मिक हों या न हों, सौहार्दपूर्ण हृदय विकसित करना और एक अच्छा इंसान बनना फायदेमंद है। जिस क्षण से हम पैदा हुए हैं, हमारी माताओं ने प्यार और स्नेह से हमारी देखभाल की है। इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं रहा है। है कि नहीं? यह स्वाभाविक रूप से और सहज रूप से आया है।'

परम पावन ने कहा, 'इसलिए हम तिब्बती दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं। यदि हम अपनी संस्कृति और मूल्यों को तेजी से और व्यापक रूप से प्रचारित-प्रसारित करते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि इससे बहुत से लोगों को लाभ होगा। मैं यहां इस बात को और स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं किसी को भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आग्रह नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं एक करुणापूर्णदिल विकसित करने की बात कर रहा हूं।'

परम पावन ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा,आजमैं जो लोग इस बैठक में उपस्थति हैं, उन सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि तिब्बती संस्कृति के सार को पुनर्जीवित करने और आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचार करें। क्योंकि यह परोपकार की संस्कृति है। यदि आप शिक्षण संस्थानों में छात्रों को करुणा और ईमानदारी जैसे मानवीय मूल्यों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए काम कर सकते हैं तो यह और भी फायदेमंद होगा। अभी के लिए बस इतना ही - धन्यवाद!'

• असम में राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग

dalailama.com, २१ जून २०२२

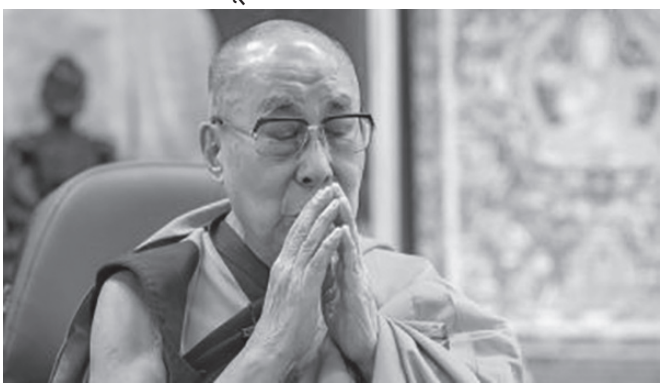

परम पावन दलाई लामा।

थेकछेन छोलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिश्व सरमा को लिखे एक पत्र में परम पावन दलाई लामा ने असम में अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ से हुई जानमाल की व्यापक हानि पर चिंता व्यक्त की है। बारिश और बाढ़ के कारण पिछले एक सप्ताह में बड़ी मात्रा में संपत्ति नष्ट हुई है और लाखों लोग बेघरबार हो गए हैं।

उन्होंने लिखा, यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि असम समेत भारत के कई हिस्सों में मानसून की बारिश साल-दर-साल कहर बरपा रही है।

"मैं हाल ही में आई बाढ़ के कारण आपके राज्य के लोगों को हुई कठिनाई के बारे में सुनकर बहुत दुखी हूं। मैं अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों और बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

'मैं उन सभी संबंधित एजेंसियों की सराहना करता हूं कि जो प्रभावित लोगों को बचाने और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं। असम के लोगों के साथ अपनी एकजुटता के प्रतीक के रूप में मैं इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए दलाई लामा के गादेन फोडरंग ट्रस्ट से दान कर रहा हूं।

• कैद तिब्बती भिक्षु को परिजनों से मिलने की अनुमति नहीं मिली,उन्हें जेल में 'देशभक्ति शिक्षा' और 'कठोर श्रम' के लिए भेजा

tibet.net, १६ जून २०२२

हालिया रिपोर्टों में सामने आया है कि चीनी अधिकारी अभी भी रिनचेन त्सुल्ट्रिम को उनके परिवार के लोगों से मिलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।अधिकारी उन्हें 'देशभक्ति शिक्षा' की कक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उनसे 'कठोर श्रम' करवा रहे हैं।

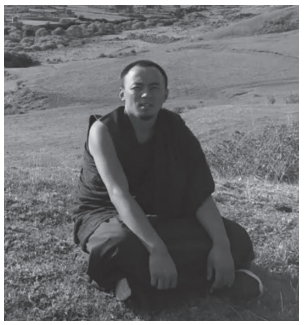

नांगशिंग मठ के भिक्षु रिनचेन त्सुल्ट्रिम।

नांगशिंग मठ के भिक्षु रिनचेन त्सुल्ट्रिम को शुरू में २७ जुलाई २०१९ को न्गाबा पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के चीनी अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किया था। उन्हें एक गुप्त मुकदमे में सजा दिए जाने की सूचना मिली थी। इसमें उन्हें तनहाई कैद में दो साल रखने के बादमार्च २०२१ में साढ़े चार साल कैद की सजा सुनाई गई।

तिब्बत टाइम्स के अनुसार, रिनचेन त्सुल्ट्रिम अधिकारियों की अनुमति लेकर अपने परिवार से महीने में दस मिनट फोन पर बात कर सकते हैं। हालांकि, चीनी अधिकारियों ने नगाबा (चीनी: अबा) में अचानक गिरफ्तार करने के बाद से रिनचेन को उनके परिवार के साथ आमने-सामने बैठकर बात करने की अनुमति देने से लगातार इनकार करतेआ रहे हैं।

रिपोर्ट में एक रिहा हो चुके एक पूर्व कैदी का हवाला देते हुए कहा गया है, 'रिनचेन अपने माता-पिता की तस्वीर लेना चाहते हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा जब्त किए जाने के डर से कुछ भी भेजने से मना करते हैं।' रिनचेन को फिलहाल चेंगदू शहर के पास मियांयांग जेल में रखा गया है।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि रिनचेन को जेल में जबरन 'राजनीतिक शिक्षा' की कक्षाओं में भेजा जा रहा है और उनसे कड़ी मेहनत करवाई जा रही है। वर्तमान में उन्हें इन गतिविधियों में कितनी बार और किस हद तक लगाया जाता है, इसके बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उनकी वर्तमान कुशल-क्षेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि न्गाबा के कीर्ति मठ के एक भिक्षु और गोलोग के एक व्यापारी सहित दो तिब्बतियों को इस साल मार्च में मियांयांग जेल से रिहा किया गया था। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में और जानकारी छिपाई गई।

पूर्वी तिब्बत में सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू के पास स्थितमियांयांग जेल में असहमतिपूर्णविचारोंऔर मतभेद रखने वाले कई तिब्बतियों को कैद में रखा गया है। जनवरी २०१९में मियांयांग जेल से सजा पूरी होने से पहले रिहा कर दिए गए एक तिब्बती भिक्षु और पूर्व राजनीतिक कैदीचोएक्यी की मई २०२०में मृत्यु हो गई।इस तरह से जेल में यातना और दुर्व्यवहार के कारण हिरासत में हुई उनकी मौत की जिम्मेदारी से चीनी सरकार पाक-साफ बच निकली।

• हाल की सजाओं ने तिब्बती बुद्धिजीवियों और लेखकों पर चीन के निरंतर दमन को साबित कर दिया

tibet.net, २१ जून २०२२

तिब्बती बुद्धिजीवियों और लेखकों को चीनी सरकार द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा है। चीनी सरकार गिरफ्तार करने के बाद महीनों गुप्त हिरासत में रखती है फिर उन्हें लंबी जेल की सजा से दंडित किया जाता है। तिब्बतियों को केवल अपनी राष्ट्रीय पहचान उजागर करने और तिब्बती भाषा और संस्कृति की रक्षा के अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और लंबी जेल की सजा सुनाई जाती है। सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि उन्होंने 'अलगाववाद का काम' किया है।

तिब्बत के लेखक चीनी पुलिस की निरंतर निगरानी के साथ-साथ इंटरनेट आधारित सेंसरशिप में रहते हैं। चीनी अधिकारी उनकी हर चीज की बारीकी से जांच करते हैं और चीनी सरकार द्वारा परिभाषित 'अवैध' या 'राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालनेवाली' किसी भी सामग्री के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। चीनी अधिकारियों के अनुसार, 'अवैध' माने जाने वाले लेखन की परिभाषा बहुत व्यापक और अस्पष्ट है। इससे उनके लिए उन तिब्बतियों को

गिरफ्तार करना आसान हो जाता है, जिन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए खतरा माना जाता हो।

तिब्बती बुद्धिजीवियों और लेखकों पर चीन के निरंतर दमन पर चिंतन।

अधिकांश तिब्बती लेखकों की गिरफ्तारी के मामलों में इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि उनके लेखन के किस हिस्से में 'अलगाववाद का कार्य' और 'राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने' वाली बात है। चीनी सरकार का हमेशा से यह विशेषाधिकार रहा है कि वह तिब्बती अदालतो द्वारा दी गई सजाओं को आसानी से नजरअंदाज कर कैदियों को असाधारण सजा भुगतने को मजबूर कर दे।

कुछ उदाहरण के रूप में दिए जा सकनेवाले हालिया मामलों में प्रसिद्ध कवि और लेखक रोंगवो गेंडुन ल्हुंडुप, प्रशंसित लेखक थुप्टन लोडो (जिसे सबुचे के नाम से भी जाना जाता है)और रोंगवो गंगकर को दी गई सजाओं को लिया जा सकता है। इनमें पहले के दो को क्रमशः चार साल और साढ़े चार साल की सजा मिली है, जबकि गंगकर को चीनी हिरासत में रखे जाने की पुष्टि की गई है। अधिकांश मामलों में आरोपों, सजा की तारीखों और उनकी वर्तमान स्थितियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई हैं।

टीसीएचआरडी ने विश्वसनीय स्रोतों के हवाले से बताया है कि प्रसिद्ध तिब्बती लेखक रोंगवो गेंडुन ल्हुंडुपको दिसंबर २०२०से नहीं देखा गया है उनको 'अलगाववाद उकसाने' के लिए चार साल जेल की सजा सुनाई गई है। ४८ वर्षीय रोंगवो गेंडुन ल्हुंडुप को ०१दिसंबर २०२१को ज़िनिंग इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट द्वारा चार साल के कारावास और दो साल तक राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने की सजा सुनाई गई थी। चीनी सुरक्षा अधिकारियों ने ११नवंबर २०२०को रोंगवो गेंडुन ल्हुंडुप को किंघई प्रांत के माल्हो (चीनी: हुआंगनान) तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर के रेबगोंग (चीनी: टोंगरेन) शहर स्थित रोंगवो मठ से हिरासत में लिया था।

मई में यह भी बताया गया था कि गेंडुन ल्हुंडुप को सिलिंग (चीनी: झिनिंग) में एक हिरासत केंद्र में रखा जा रहा है। उन्हें 'राजनीतिक पुन:शिक्षा कार्यक्रम' में भेजा गया है, जहां उन्हें तिब्बती बौद्ध ग्रंथों का मंदारिन-चीनी में अनुवाद करने का काम दिया गया है।

'खोरवा' (संसार की बौद्ध अवधारणा, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र का वर्णन करती है) नामक कविताओं के अपने नवीनतम संग्रह को प्रकाशित करने के बादउन्हें हिरासत में लिया गया और सजा सुनाई गई। पूर्व में कई बार गिरफ्तार होने के साथ-साथ उनकी गिरफ्तारी के दौरान उन पर कड़ी निगरानी और पाबंदियां भी लगाई गई थीं।

३४ वर्षीय प्रशंसित तिब्बती लेखक थुप्टेन लोडो को १४ जून २०२२ के आसपास 'अलगाववाद भड़काने'के झूठे आरोपों में चीनी सरकार द्वारा साढ़े चार साल की सजा सुनाई गई थी। पिछले साल गिरफ्तारी के बाद आठ महीनों से वह अज्ञात स्थान पर बंद हैं।

मीडिया में आ रही रिपोर्ट में कहा गया है कि, थुप्टन लोडो उर्फ सबुचे को शुरू में पिछले साल अक्तूबर में 'देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली' और 'जातीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली' सामग्री लिखने और प्रकाशित करने के संदेह में हिरासत में लिया गया था। 'अलगाववाद भड़काना'चीनी सरकार द्वारा तिब्बतियों, विशेष रूप से बुद्धि जी वियों और लेखकों, मानवाधिकार रक्षकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ सबसे आम आरोपों में से एक है। पिछले साल प्रमुख तिब्बती लेखकों और विद्वानों के खिलाफ भी यही आरोप लगाया गया था, जिनमें गो शेरब ग्यात्सो, रिनचेन त्सुल्ट्रिम, धी ल्हादेन और रोंगवो गेंडुन ल्हुंडुप शामिल हैं।

तिब्बती सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी (टीसीएचआरडी) की रिपोर्ट के अनुसार, सबुचे की गिरफ्तारी पर अधिक जानकारी हासिल करने के लिए किए जानेवाले किसी भी प्रयास और छानबीन को चीनी सरकार के डर के कारण छोड़ दिया गया था। असल में चीनी सरकार ने सूचनाओं के आदान-प्रदान पर प्रतिबंध लगा दिया है धमकी दी है कि अगर परिवार और रिश्तेदारों ने कोई जानकारी इधर-उधर सार्वजनिक की तो उनपर भी ये प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

हालांकि उन्हें सजा सुनाई गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कहां रखा गया है और वह किस स्थिति में हैं। एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार, उनके परिवार को वर्तमान में स्थानीय अधिकारियों द्वारा धमकाया जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है। साथ ही उनके बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं है।

रोंगवो गंगकर

एक हालिया रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि तिब्बती लेखक और विद्वान रोंगवो गंगकर को २०२१ की शुरुआत से एक साल से अधिक समय तक लापता रहने के बाद चीनी सरकार ने हिरासत में लिया है।

रेडियो फ्री एशिया (आरएफए) की रिपोर्ट के अनुसार, ४८ वर्षीय लेखक को २०२१ की शुरुआत में चीनी अधिकारियों ने अचानक गिरफ्तार कर लिया था और उनका वर्तमान ठिकाना और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अज्ञात है। उनकी गिरफ्तारी के बाद, चीनी पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें हिरासत में ले लिया।

चीनी सरकार की ओर से न तो उन पर लगे आरोपों और न ही उनके मुकदमे की तारीख का खुलासा किया गया है।

रोंगवो गंगकर की एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है, जिनके नाम के प्रकाशन बड़ी संख्या में हैं। मूल रूप से माल्हो (हुआंगनान) तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर में रेबगोंग (चीनी: टोंगरेन) काउंटी के रहने वाले गंगकर रोंगवो मठ से संबंधित है। उनकी लोकप्रिय रचनाओं में 'द नॉट' और 'एन इंटरव्यू विद गेंडुन चोफेल' प्रमुख हैं।

हाल में दी गई इन सजाओं से यह स्पष्ट है कि चीनी सरकार तिब्बती बुद्धिजीवियों और विद्वानों को तिब्बती भाषा के संरक्षण की हिमायत करने

की उनकी क्षमता को कमजोर करने के लिए व्यवस्थित रूप से अभियान चला रही है। उन तिब्बती लेखकों और विद्वानों की एक लंबी सूची है जिन्हें चीनी सरकार द्वारा केवल अपनी राष्ट्रीय पहचान का दावा करने और मौलिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए गिरफ्तार किया गया या सजा सुनाई गई है। इनमें गो शेरब ग्यात्सो, धी ल्हादेन, रोंगवो गेंडुन ल्हुंडुप, पेमा त्सो, सेयनम, रिनचेन त्सुल्ट्रिम और कुनसांग ग्यालत्सेन शामिल हैं। उनमें से कुछ को लंबी कारावास की सजा भी दी गई हैं।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार को अपनी सांस्कृतिक अस्मिता नीति को रोकना चाहिए और सभी तिब्बती लेखकों, बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक नेताओं को तुरंत और बिना शर्त रिहा करके मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए और उनकी विचार, विवेक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को फिर से स्थापित करना चाहिए।

• युवा तिब्बती लोडो की मनमानी गिरफ्तारी के ६ महीने बाद भी उनका परिवार अंधेरे में

(अपनी गिरफ्तारी से पहले लोडो ने तिब्बती भाषा के संरक्षण के लिए चीनी सरकार की नौकरी के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था।)

rfa.org / संग्याल कुंचोक, १६ जून २०२२

लोडो।

तिब्बत के अंदरके सूत्रों ने आरएफए को बताया कि चीनी अधिकारियों ने छह महीने पहले एक युवा तिब्बती भाषा कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया था। लेकिन उसकी स्थिति और ठिकाने के बारे भी आज तक उसके परिवार तक को पता नहीं है।

अपनी उम्र के तीसरे दशक में चल रहे थुप्टेन लोडो (उन्हें सबुचे के नाम से भी जाना जाता है)सिचुआन प्रांत में गारज़े (गांज़ी) तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरके सेशुल काउंटी (चीनी शिक) में एक विश्वविद्यालय के स्नातक हैं। दो बच्चों के पिता लोडो चीनी, अंग्रेजी और तिब्बती भाषा में पारंगत हैं और यह ज्ञात है कि उन्होंने तिब्बती आध्यात्मिक नेता पंचेन लामा द्वारा स्थापित एक स्कूल में पढ़ाई की है। चीनी सरकार ने उन्हें नौकरी स्वीकार करने के लिए १०,००० युआन (१४८९ अमेरिकी डॉलर) की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने तिब्बती भाषा के संरक्षण के लिए ठुकरा दिया।

"तब से, उनके बारे में कोई जानकारी ज्ञात नहीं है। उनके परिवार को कुछ स्रोतों से पता चला है कि उन्हें जल्द ही दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन वे अभी भी नहीं जानते हैं कि इस समय उन्हें वास्तव में कहां हिरासत में रखा जा रहा है- जेल में या किसी हिरासत केंद्र में।

• चीनी अधिकारियों ने निर्वासित तिब्बतियों से संपर्क करने के आरोप में तिब्बती छात्र को तीन साल की सजा सुनाई

'देश की गोपनीय सूचनाओं' को उजागर करने के आरोप में तिब्बती बुद्धिजीवियों पर कार्रवाई की शृंखला में न्यिमा की सजा नवीनतम है।

rfa.org / संग्याल कुंचोक, २८ जून, २०२२

न्यिमा

चीनी अधिकारियों ने इस महीने निर्वासित तिब्बतियों से संपर्क करने के आरोप में विश्वविद्यालय के एक छात्र को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। आरएफए की तिब्बती सेवा को कार्यकर्ताओं ने यह जानकारी दी है। इस छात्र को दी गई सजा तिब्बती बुद्धिजीवियों, कलाकारों और तिब्बती समुदाय के अन्य नेताओं की मनमानी गिरफ्तारी की शृंखला में नवीनतम घटना है।

न्यिमा नामक इस छात्र को जासूसी के आरोप में इस साल जनवरी में सिचुआन प्रांत के कार्दज़े (चीनी: गंजी) तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर के शेलियन टाउनशिप से अप्रत्याशित रूप से गिरफ्तार किया गया था।

न्यिमा सिचुआन के गेहो नेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और वह तिब्बती संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। तिब्बती, चीनी और अंग्रेजी में धाराप्रवाह बोलने का ज्ञान रखनेवाले न्यिमा जनवरी में अपनी गिरफ्तारी से पहले तक हमेशा पर्यटकों और आगंतुकों के संपर्क में रहते थे और उन्हें तिब्बत की अनूठी भाषा और संस्कृति के बारे में जानकारियां देते रहते थे।

तिब्बत के अंदर रहने वाले एक तिब्बती सूत्र ने आरएफए को बताया, कि न्यिमा को कथित तौर पर राष्ट्रीय गोपनीय सूचनाओं को लीक करने के आरोप में गत ०५ जून को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि चीनी अधिकारियों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि न्यिमा ने किस तरह की राष्ट्रीय गोपनीय सूचनाओं को लीक किया है।

सूत्र ने सुरक्षा कारणों से नाम न छापने का अनुरोध करते हुए बताया कि उन्हें तिब्बत के इतिहास और प्रामाणिक तिब्बती संस्कृति के बारे में पर्यटकों को जानकारी देते हुए देखा जा सकता था, इसलिए मुझे लगता है कि यह उनकी गिरफ्तारी का कारण हो सकता है। उनके परिवार को पता नहीं है कि वह इस समय कहाँ कैद हैं।

लंदन स्थित तिब्बत वॉच एडवोकेसी ग्रुप के एक शोधकर्ता पेमा ग्याल ने आरएफए की तिब्बती सेवा को बताया कि न्यिमा की गिरफ्तारी अन्य दूसरे गणमान्य तिब्बतियों की गिरफ्तारी के समान है।

पेमा ग्याल ने कहा कि चीनी सरकार द्वारा तिब्बत के अंदर तिब्बती बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी के मामले बढ़ते जा रहे है और हमने न्यिमा के मामले में देखा है कि उन्हें बाहरी निर्वासित समुदाय के साथ संपर्क रखने और तिब्बती भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए भी गिरफ्तार किया गया है।

सूत्रों का कहना है कि हाल के वर्षों में तिब्बती राष्ट्रीय अस्मिता का दावा करने के प्रयासों में भाषा अधिकार विशेष फोकस बन गया है। संगठित भाषा पाठ्यक्रमों को आमतौर पर अनौपचारिक रूप से 'अवैध गतिविधि' माना जाता है और इसके शिक्षकों को हिरासत में लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है।

लोडो की गिरफ्तारी चीनी सरकार द्वारा तिब्बती लेखकों, बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक नेताओं पर की जा रही बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों ने उनके परिजनों को

सटीक आरोप या उनकी सजा की तारीखों के बारे में बताए बिना ही लंबे समय से अज्ञात स्थानों में कैद कर रखा है।

सूत्र ने कहा, 'आम तौर पर संबंधित काउंटी के अधिकारी आते हैं और व्यक्तियों को उठाकर हिरासत में ले जाते हैं।'

'हालांकि, इस बार सिचुआन प्रांत के चीनी अधिकारी लोडो को गिरफ्तार करने आए थे। बहुत से लोग मानते हैं कि लोडो को निर्वासित तिब्बतियों के साथ संपर्क और संवाद रखने और तिब्बती भाषा के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया। हालांकि,चीनी अधिकारियों ने अभी तक उन की गिरफ्तारी के लिए कोई कारण नहीं बताया है। (या तो) हम अभी भी उसकी गिरफ्तारी का सही महीना और तारीख नहीं जानते।

चीन में रहने वाले लोदो के एक दोस्त ने आरएफए को बताया कि चीनी सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार को धमकी दी थी।

'परिवार को कहा गया था कि वे किसी से भी इस मामले पर चर्चा न करें। उनके दो बच्चों को भी स्कूल जाने से रोक दिया गया था और उसके परिवार को वर्तमान में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

२००८ में चीन के पश्चिमी प्रांत तिब्बत और तिब्बती क्षेत्रों में चीनी शासन के खिलाफ व्यापक विरोध उठ खडे होने के बाद चीनी अधिकारियों ने तिब्बती राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले तिब्बती लेखकों और कलाकारों को अक्सर हिरासत में लिया है,जिनमें से कई को लंबी सजा सुनाई गई है। सूत्रों का कहना है कि हाल के वर्षों में तिब्बतियों द्वारा अपनी राष्ट्रीय पहचान का दावा करने के लिए भाषा अधिकार विशेष फोकस बन गया है। अनौपचारिक रूप से संगठित भाषा पाठ्यक्रमों की कक्षाओं को आम तौर पर 'अवैध संघ' माना जाता है और शिक्षकों को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में ले लिया जाता है।

• परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म के बारे में निर्णय लेने का अधिकार स्वयं परम पावन और तिब्बतियों के पास:सिक्योंग

tibet.net, २३ जून २०२२

धर्मशाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने २२ जून को तिब्बत पर आठवें विश्व सांसद सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें चीन-तिब्बत संवाद से लेकर परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म तक के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई।

आठवें विश्व सांसद सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिक्योंग पेन्पा छेरिंग।

तिब्बत मुद्दे पर अमेरिकी सरकार द्वारा की गई पहलों और समान विचारधारा वाले देशों द्वारा अपने-अपने संसदों में इसी तरह के कदम की अपेक्षा पर प्रकाश डालते हुए सिक्योंग ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति और वैश्विक राजनीति में बाद के बदलावों के बाद चीन पर दुनिया के बदलते दृष्टिकोण ने उग्यूर, मंगोलियाई, हांगकांग और ताइवान के जागरूक लोगों के साथ तिब्बतियों को भी नई वैश्विक व्यवस्था में उभरते अवसरों और चुनौतियों लाभ उठाने का अवसर दिया है।

सम्मेलन के दौरान सांसदों की सक्रिय भागीदारी और उनके अपने देश की संसदों में तिब्बत आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनकी रुचि की अभिव्यक्ति की सराहना करते हुए सिक्योंग ने चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने में मदद करने को तत्पर रहनेवाले सभी लोगों और देशों के लिए एक साझा मंच बनाने के लिए इस सम्मेलन को आगे भी जारी रखने पर जोर दिया। इसके अलावा, सिक्योंग ने एक अन्य सत्र में चीन के मजबूत और व्यापक प्रचार और इसके द्वारा दिए जानेवाले गलत दिशा-निर्देशों की आशंका को देखते हुए तिब्बत पर बदलते नजरिए को लेकर मुकम्मल चर्चा कराने के बारे में सम्मेलन को बताया।

चीन के विस्तार के बारे में बोलते हुए सिक्योंग ने दोहराया कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था जो माइकल वैन वॉल्ट वैन प्राग, प्रोफेसर लाउ हान शियांग और अन्य शोधकर्ताओं के निष्कर्षों में आईने की तरह चमकता है। हालांकि, सिक्योंग ने उल्लेख किया कि परम पावन दलाई लामा के नेतृत्व वाले तिब्बतियों ने सर्वसम्मति से जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान के रूप में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण को अपनाया है।

अतीत में तिब्बत को एक स्वायत्त देश के रूप में प्रमाणित करने के लिए इतिहासकारों द्वारा स्थापित साक्ष्यों को दरकिनार करके चीनी सरकार द्वारा वार्ता के दौरान परम पावन दलाई लामा के समक्ष रखे गए उस पूर्व शर्त को सिक्योंग ने याद किया, जिसमें चीन ने परम पावन से यह स्वीकार करने को कहा था कि तिब्बत अति प्राचीन काल से ही चीन का अभिन्न अंग रहा है। परम पावन ने इसका बुद्धिमानी से उत्तर देते हुए कहा था,'मैं इतिहासकार नहीं हूं, आइए इतिहास को इतिहासकारों पर छोड़ दें। हमारे लिए जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है तिब्बती लोगों का भविष्य।'

तिब्बत पर चीन के निरंतर दावे के पीछे के उद्देश्यों को उजागर करते हुए सिक्योंग ने कहा, 'चीन तिब्बत पर कब्जे की अपनी वैधता साबित करने की कमजोरियों को जानता है। इसीलिए वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसकी वैधता की पुष्टि कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन, दुर्भाग्य से अंतरराष्ट्रीय समुदाय तिब्बत पर चीन की वैधता को स्वीकार नहीं कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा,'तिब्बत पर चीनी कब्जे को वैधता केवल तिब्बती लोग या परम पावन दलाई लामा ही दे सकते हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ देशों द्वारा चीन के तथाकथित घरेलू मुद्दे में हस्तक्षेप करने से परहेज करने की अपील के साथ ही कुछ देशों द्वारा चीन-तिब्बत वार्ता का समर्थन करने की बात करने से तिब्बतियों के बीच विरोधाभासी भावनाएं उभर कर आई हैं। इसलिए, सिक्योंग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सम्मेलन में मौजूद सांसद तिब्बत के चीन का हिस्सा नहीं होने के संदेश को वापस अपने देशों में ले जाएंगे।

तिब्बत में औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना की हालिया रिपोर्टों में उभर कर सामने आई तिब्बती पहचान को मिटाने की राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीति को देखते हुए सिक्योंग ने कहा कि चीन कभी भी वार्ता की मेज

पर आने के लिए उत्सुक नहीं होगा और अंततः मध्यम मार्ग के लाभ को बाधित करेगा। इसलिए, उन्होंने सांसदों से तिब्बत में चीन के लौह जकड़न नीति पर सवाल उठाने का आग्रह किया।

इसके अलावा, सिक्योंग ने उपस्थित सांसदों को तिब्बत के पर्यावरण, विशेष रूप से इसके जल संसाधन के चीन द्वारा शोषण के महत्व पर प्रकाश डाला। तिब्बत की नदियों पर चीन के बड़े बांधों के निर्माण और इसके निहितार्थों के बारे में और नवीनतम जानकारियों के साथ उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की गतिविधियां, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप सेनिचले इलाकों के देशों की आजीविका को प्रभावित करती हैं, जिनके साथ चीन आमतौर पर अपने जल विज्ञान से संबंधित आंकड़ों को साझा करने से इनकार करता रहा है।

इसके अलावा, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदायों को चीन द्वारा चीजों के चीनीकरण के प्रयासों से बचने के लिए उग्यूर के बजाय इस क्षेत्र को पूर्वी तुर्केस्तान झिंझियांग कहने का आग्रह किया। साथ ही तिब्बत के लिए ज़िज़ांग नाम से दुनिया की अनभिज्ञता के बारे में भी चर्चा की। साथ ही, उन्होंने सम्मेलन में उग्यूर राजनेता और कार्यकर्ता डोलकुन ईसा, हांगकांग और मंगोल के तिब्बत के दोस्तों की उपस्थिति को स्वीकार किया, जिनके साथ तिब्बती प्रतिनिधि अपने साझा प्रतिद्वंद्वी सामूहिक तौर परचुनौती देने के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने पर चर्चा करेंगे।

इन टिप्पणियों के साथ सिक्योंग ने विशेष रूप से परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म के मुद्दे की ओर इशारा करते हुए कहा कि परम पावन के पुनर्जन्म को निश्चित करने की जिम्मेदारी और इसका अधिकार पूरी तरह से परम पावन दलाई लामा और तिब्बती लोगों के पास है।

अपना संबोधन समाप्त करने से पहले सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने सम्मेलन में सांसदों की भागीदारी के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया।

• सिक्योंग ने वाशिंगटन में तिब्बत के प्रतिनिधि कार्यालयों की बैठक की अध्यक्षता की

tibet.net, २६जून २०२२

वाशिंगटन। अमेरिका की दो सप्ताह के दौरे पर आए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने आठवें डब्ल्यूपीसीटी के सफल समापन के बाद शुक्रवार २४जून को तिब्बत के कार्यालयों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दो दिवसीय बैठक में सिक्योंग के साथ डीआईआईआर कालोन नोरज़िन डोल्मा और डीआईआईआर सचिव कर्मा चोयिंग भी शामिल हुए। बैठक में अन्य बातों के अलावा, प्रतिनिधियों ने अपने-

डीआईआईआर सूचना अनुभाग के अतिरिक्त सचिव नामग्याल छेवांग और ओओटी वाशिंगटन डीसी के कर्मचारी के साथ सिक्यांग पेन्पा छेरिंग।

अपने मेजबान देशों में स्वैच्छिक तिब्बती एडवोकेसी समूह (वी-टैग) की कूटनीति और इसके कार्यों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।साथ ही १६वें कशाग की आगामी जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण पहल के बारे में भी चर्चा हुई। बैठक में डीआईआईआर सूचना अनुभाग के अतिरिक्त सचिव नामग्याल छेवांग और ओओटी वाशिंगटन डीसी के कर्मचारी भी उपस्थित थे।

• तिब्बत के लिए सांसदों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के पुनरुद्धार के साथ तिब्बत पर आठवें विश्व सांसद सम्मेलन का समापन

tibet.net, २४ जून २०२२

वाशिंगटन डीसी। निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा आयोजित तिब्बत पर आठवां विश्व सांसद सम्मेलन २३ जून २०२२ को तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय सांसदों के नेटवर्क (आईएनपीएटी) के सफल पुनरुद्धार,वाशिंगटन घोषणा और वाशिंगटन कार्य योजना को पारित करने के साथ संपन्न हो गया।

तिब्बत पर कथाएं: परिवर्तन की आवश्यकता' विषय पर एक पैनल चर्चा में कनाडा के सांसद आरिफ विरानी, प्रो. हो-शियांग लाउ, प्रो. माइकल वैन वॉल्ट पराग, भारत के सांसद डॉ. शशि थरूर, और कलोन नोरज़िन डोल्मा

तिब्बत पर विधि निर्माताओं के दो दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन ताइवान के सांसद और समाज कल्याण और पर्यावरण स्वच्छता समिति के सदस्य हंग सुन-हानऔर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन में तिब्बत नीति संस्थान के पर्यावरण और विकास डेस्क के रिसर्च फेलो डेचेन पाल्मो ने 'ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में एशिया और तिब्बत के महत्व'पर बात की। तिब्बती सांसद तेनजिंग जिग्मे ने इस सत्र की अध्यक्षता की।

भारतीय लोकसभा सदस्य और पूर्व भारतीय विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर, कनाडा के सांसद और कनाडा के तिब्बत संसदीय मित्र (पीएफटी) के अध्यक्ष आरिफ विरानी, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर और क्रेधा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. माइकल वैन वॉल्ट प्रागऔर सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ़ हांगकांग के सेवानिवृत्त चेयर प्रोफेसर प्रो. मान-शियांग लाउने एक पैनल चर्चा में 'तिब्बत पर कथाएं: परिवर्तन की आवश्यकता' पर बात की। इस बैठक की अध्यक्षता सीटीए के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग (डीआईआईआर) के कालोन नोरज़िन डोल्मा ने की।

अल सल्वाडोर की संसद सदस्य जॉन टेनेंट राइट सोल की अध्यक्षता में कई देशों के अनेक सांसदों ने पैनल चर्चा के दौरान 'समान विचारधारा वाले देशों के बीच अनुभव, सहयोग, नेटवर्किंग और कार्य योजनाओं को साझा करने'पर अपने विचार साझा किए। स्विट्जरलैंड से संसद सदस्य और स्विट्जरलैंड के तिब्बत संसदीय समूह के सह-अध्यक्ष निकोलस वाल्डर, स्विट्जरलैंड से संसद सदस्य और तिब्बत के लिए स्विस संसदीय समूह के सदस्य

बलथासर ग्लैटली, तिब्बत के लिए स्कॉटिश पार्लियामेंट सर्वदलीय समूह के सदस्य स्कॉटलैंड से संसद सदस्य कोलेट स्टीवेन्सन,; लिथुआनिया से सांसद लाईमा लिउसिजा एंड्रिकिएन; ब्रिटेन के संसद सदस्य टिम लॉटन और क्रिस लॉ, इंग्लैंड में तिब्बत के लिए सर्वदलीय संसदीय समूह के सह-अध्यक्ष सांसद सर इयान डंकन स्मिथ, डेनमार्क से सांसद और आईपीएसीके सह-संस्थापकउफ्फे एल्बेक,भारतीय सांसद और तिब्बत के लिए सर्वदलीय भारतीय संसदीय मंच के संयोजक सुजीत कुमारऔर जर्मन पार्लियामेंट्री फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत के अध्यक्ष जर्मन सांसद माइकल ब्रैंडने इस पर अपनी टिप्पणी दीं।

कनाडा के सांसद और कनाडा के पॉर्लियामेंटरी फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत के उपाध्यक्ष जेम्स मैलोनी, कोस्टा रिका के सांसद ग्लोरिया नवास मोंटेरो,मेक्सिको के संसद सदस्य सल्वाडोर कारो कैबरेरा,स्पेन के सांसद रॉबर्ट मसीह नाहरऔर चेक गणराज्य के सांसद मारेक हिल्सर ने 'समान विचारधारा वाले देशों के बीच अनुभव, सहयोग, नेटवर्किंग और कार्य योजनाओं को साझा करने'पर बात की।इसके बाद सांसदों के बीच चर्चा हुई।

एकसमान चुनौतियों का सामना करने के लिए 'कॉमन ग्राउंड' पर पैनल चर्चा के दौरान ताइवान के सांसद त्सिओंग-त्सो लिम,विश्व उग्यूर कांग्रेस के अध्यक्ष डोलकुन ईसा,हांगकांग लोकतंत्र परिषद श्री जेफरी न्गो और चीन संवाद के अध्यक्ष वांग डैन ने इस विषय पर बात की। सत्र की अध्यक्षता तिब्बती सांसद तेनजिन जिगदल ने की।

सम्मेलन के समापन के अवसर पर डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग ने औपचारिक रूप से तिब्बत पर अंतरराष्ट्रीय सांसदों के नेटवर्क (आईएनपीएटी) के पुनरुद्धार की घोषणा की और प्रतिभागी सांसदों की उपस्थिति में अपनी आधिकारिक वेबसाइट (www.inpat.org) लॉन्च की।

इसके बादक्रेधा के कार्यकारी अध्यक्ष और सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के सोमपोंग सुचरितकुल सेंटर फॉर एडवांस्ड इंटरनेशनल लीगल स्टडीज में सीनियर फेलो प्रो. माइकल वैन वॉल्ट प्राग ने मसौदा समिति के अन्य सदस्यों के साथवाशिंगटन डीसी घोषणा और वाशिंगटन कार्य योजना प्रस्तुत की जिसे बाद में उचित विचार-विमर्श के बाद पारित कर दिया गया था। अल सल्वाडोर, चिली और मैक्सिको के लैटिन अमेरिकी सांसदों की एक संयुक्त घोषणा को अल सल्वाडोर के संसद सदस्य जॉन टेनेंट राइट सोल ने पढ़ा।

अंत में, निर्वासित तिब्बती संसद की उपाध्यक्ष डोल्मा छेरिंग तेखांग ने सम्मेलन में आए सांसदों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और उनका आभार माना। इन सांसदों की सम्मेलन में उपस्थिति ने बीजिंग को एक मजबूत संदेश दिया है। साथ ही इससे तिब्बत के अंदर तिब्बतियों का मनोबल भी बढ़ेगा।

चीन से फैलने वाले कोविड -१९ के उदाहरण से चीनी कम्युनिस्ट सरकार की धोखेबाजी को समझाते हुए तिब्बती संसद की उपाध्यक्ष ने चेतावनी दी और जोर देकर कहा कि शी जिनपिंग जैसी विस्तारवादी मानसिकता के साथ सत्ता पर काबिज नेताओं से स्वतंत्र दुनिया में रहने वाले लोगों द्वारा उपभोग की जा रही स्वतंत्रता, मुक्तिऔर मानवाधिकारों जैसे अधिकारों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

कम्युनिस्ट शासन के तहत दबाए जा रहे चीनी नागरिकों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि चीन के आम लोगों को वहां के कम्युनिस्ट नेतृत्व द्वारा तिब्बती लोगों की तरह ही उत्पीड़ित किया जाता है। डिप्टी स्पीकर ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में आम पीड़ा को प्रसारित करने के लिए उग्यूर, हांगकांग, ताइवान, आंतरिक मंगोलियाई और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों को आपस में जुड़े रहकर सामूहिक प्रयास करते रहने का आह्वान किया।

उन्होंने सम्मेलन में आए सांसदों, आयोजन समिति, आईसीटी, सिक्योंग के नेतृत्व वाले कशाग, डीआईआईआर कालोन, तिब्बत के कार्यालयों, एनईडी, एनडीआई, मसौदा समिति और अन्य सभी को सम्मेलन के आयोजन में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए अपने संबोधन का समापन किया।

इससे पहले दिनमें तिब्बती निर्वासित संसद की डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी राजधानी में तिब्बत को लेकर अमेरिकी कांग्रेस की 'चीन पर कांग्रेस-कार्यकारी आयोग (सीईसीसी)' द्वारा आयोजित 'तिब्बत: एक अनसुलझे संघर्ष को सुलझाने में आ रही बाधाएं' विषय की सुनवाई में भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद कुंगा सोटोप, सांसद खेंपो काडा नेगडुप सोनम, सांसद गेशे ल्हारम्पा गोवो लोबसंग फेंडे, सांसद मिग्युर दोर्जी, सांसद गेशे एटोंग रिनचेन ग्यालत्सेन,सांसद छेरिंग डोल्मा, सांसद चोएडक ग्यात्सो के अलावा आठवें डब्ल्यूपीसीटी के कुछ अन्य प्रतिभागी भी शामिल थे। निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा आयोजित यह सम्मेलन डब्ल्यूपीसीटी के पिछले सात सत्रों की निरंतरता में था। इसका उद्देश्य तिब्बत मुद्दे को हल करने के लिए विभिन्न देशों के सांसदों के समर्थन को मजबूत और समन्वित करना रहा है। पहला डब्ल्यूपीसीटी१९९४ में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें चीन के आक्रमण और तिब्बत पर कब्जे के बाद तिब्बती पहचान और अस्तित्व के लिए भारत द्वारा निभाई गई भूमिका का सम्मान किया गया था। इसके बाद के सम्मेलन १९९५ में लिथुआनिया के विनियस, १९९७ में अमेरिका के वाशिंगटन डी.सी.,२००५ में स्कॉटलैंड (यू.के.) के एडिनबर्ग,२००९ में इटली के रोम, २०१२ में कनाडा के ओटावा, और २०१९ में लातविया के रीगा में आयोजित किए गए।

तिब्बत पर विश्व सांसद सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य सांसदों द्वारा तिब्बती पहचान और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अस्तित्व के सवालपर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाना है। तिब्बत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासतमें अधिक शांतिपूर्ण दुनिया में योगदान करने की क्षमता है। इसी तरह, सांसदों को तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और धार्मिक दमन पर चिंता व्यक्त करने में विश्व नेताओं के साथ शामिल होना चाहिए और बातचीत से तिब्बत मुद्दे के समाधान के लिए परम पावन दलाई लामा के दूतों और चीनी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की जल्द बहाली के पक्ष में अपने-अपने देशों की ओर से पहल करने पर विचार करना चाहिए।

• तिब्बत पर आठवें विश्व सांसद सम्मेलन की घोषणा

tibet.net, २४ जून २०२२
वाशिंगटन डीसी घोषणा
तिब्बत पर विश्व सांसदों का आठवां सम्मेलन
२२-२३ जून २०२२, वाशिंगटनडीसी

२८ देशों के सांसदों ने २२ से २३ जून, २०२२ तक वाशिंगटन डी.सी. में आठवें विश्व सांसद सम्मेलन में भाग लिया और तिब्बत की स्थिति की समीक्षा के साथ१९५० में तिब्बत पर पीआरसी के आक्रमण और उसके बाद से उस पर अवैध कब्जेके कारण उत्पन्न हुए चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के प्रयासों पर चर्चा की।विभिन्न देशों से आए सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस के

अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और तिब्बत पर हाल के वर्षों में अपनाए गए पथ-प्रदर्शक कानून के लिए अमेरिकी कांग्रेस की सराहना की।

बैठक २४ फरवरी को स्वतंत्र देश यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण शुरू हुए युद्ध की छाया में हुई। रूस-यूक्रेन युद्ध चौथे महीने में प्रवेश करने वाला है। इस रूसी आक्रमण की तुलना दशकों पहले तिब्बत पर चीन के आक्रमण से होने लगी है। यह आक्रमण अंतरराष्ट्रीय कानून के सबसे मौलिक मानदंडों के प्रमुख उल्लंघन का एक उदाहरण है। साथ ही यह युद्ध अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है और अल्पकालिक आर्थिक लाभों से उपर उठकर कानून के शासन की सुरक्षा और स्वतंत्रता, लोकतंत्र, आत्मनिर्णय और मानवाधिकारों को दुनिया भर में बढ़ावा को प्राथमिकता देने की जरूरत पर जोर देता है।

प्रतिभागियों ने तिब्बत से संबंधित मामलों पर विभिन्न देशों की संसदों और निर्वासित तिब्बती संसद के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई। इसमें चीन पर गठित इंटर पार्लियामेंटरी एलायंस और अन्य अंतर संसदीय संगठनों और निकायों के साथ सहयोग करना शामिल है। तिब्बत पर सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनपीएटी) को पुनर्जीवित किया जाएगा और जहां तक संभव हो सके सांसद अपने-अपने उन देशों में संसदीय समूह बनाएंगे जहां यह अभी तक गठित नहीं हुआ है।

प्रतिभागियों ने विभिन्न देशों की संसदों से इस घोषणा के अनुरूप तिब्बती मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर कानून, संकल्प या प्रस्ताव पारित करने, सुनवाई करने और जांच सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

प्रतिभागियों ने सभी संसदों से समन्वित कार्रवाई करने और तिब्बत के संबंध में अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए अपनी सरकारों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया, जिसमें निम्न अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने-अपनेदेशों के दायित्वों और जिम्मेदारियों को पूरा करना शामिल है-

• आत्मनिर्णय के तिब्बतियों के अहरणीय अधिकार को सम्मान और बढ़ावा देना,

• तिब्बत पर संप्रभुता के पीआरसी के दावे को स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से मान्यता देने से बचना,

• तिब्बत को कब्जा किया हुआ देश के रूप में मानना न कि चीन के हिस्से के रूप में, और

• बिना किसी पूर्व शर्त के पक्षों के बीच बातचीत और समझौतों के माध्यम से चीन-तिब्बत संघर्ष का समाधान करने की दिशा में अन्य समान विचारधारा वाली सरकारों के साथ समन्वित कार्रवाई करना।

प्रतिभागियों ने संसदों से अगले दलाई लामा और अन्य वरिष्ठ लामाओं के पुनर्जन्म को चुनने और उन्हें नियुक्त करने के लिए दलाई लामा, गाडेन फोडरंग ट्रस्ट, तिब्बती लोगों और तिब्बती बौद्ध समुदाय के अनन्य अधिकार की पुष्टि और समर्थन करने के लिए समन्वित कार्रवाई करने का आह्वान किया। साथ ही ऐसा करने के पीआरसी के घोषित इरादे को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के तौर पर देखकर दृढ़ता से खारिज करने की अपील भी की।

प्रतिभागियों ने पीआरसी और सीसीपी द्वारा प्रचारित उन झूठे ऐतिहासिक आख्यानों को खारिज कर दिया, जिन में तिब्बत पर पीआरसी के आक्रमण और तिब्बत के वर्तमान कब्जे को सही ठहराने का प्रयास करने के लिए दावा किया जाता है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है। प्रतिभागियों ने सांसदों और संसदों से इन झूठे आख्यानों को बेनकाब करने और उनका मुकाबला करने के लिए समन्वित कार्रवाई करने का आह्वान किया।

प्रतिभागियों ने संसदों से आह्वान किया कि वे तिब्बत के निगमों को जबरन श्रम और तिब्बती पठार के प्राकृतिक पर्यावरण के शोषण से लाभ अर्जित करने से रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई करें।

सम्मेलन में खनन के कारण तिब्बती पठार में बड़े पैमाने पर होने वाले पर्यावरणीय क्षरण का उल्लेख किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जहरीले अपशिष्ट, जल प्रदूषण पैदा हुए और वनों की कटाई से पहाड़ों का विनाश हुआ। इसके अलावा, इस शोषण को क्रियान्वित करने के लिए २० लाख से अधिक तिब्बती खानाबदोशों को उनकी पारंपरिक भूमि से हटा कर सांस्कृतिक रूप से विनाशकारी गांवों में बसाया गया है।

तिब्बत में पर्यावरणीय कुप्रबंधन के प्रभाव तिब्बत से कहीं आगे तक फैले हुए हैं, क्योंकि पठार से निकलने वाली १० प्रमुख नदियों पर चीन की ५० से अधिक विशाल बांधों के निर्माण की योजना है, जिससे नीचे के देशों में १.५अरब से अधिक लोगों की जल आपूर्ति पर संकट मंडरा रहा है।

दुनिया के तीसरे ध्रुव के रूप में तिब्बत की अवस्थिति के परिणामस्वरूप यहां ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव विश्व औसत से दोगुने से अधिक दर से होता है। इसके परिणामस्वरूप २०५० तक पठार पर के अधिकांश ग्लेशियर पिघल जाएंगे।

प्रतिभागियों ने पीआरसी शासन के तहत उग्यूर और दक्षिणी मंगोलियाई लोगों, हांगकांग के लोगों और ताइवान के लोगों के साथ-साथ पीआरसी के कोप भाजन बनने का खतरा झेल रहे चीनी लोकतंत्र आंदोलन में शामिल लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। ये सभी लोग एकसमान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इससे निपटने के लिए एक तरह के लोगों का समर्थन चाहते हैं।

प्रतिभागियों ने तिब्बतियों की लोकतांत्रिक उपलब्धियों, अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धताओं और मध्यम मार्ग के माध्यम से पीआरसी के साथ संघर्ष के समाधान की तलाश के उनके प्रयासों के प्रति अपने निरंतर समर्थन को व्यक्त किया।

• प्रो. समदोंग रिनपोछे ने तिब्बत पर लिखी 'तुम्हारा नाम क्या है-तिब्बत' शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया

tibet.net, ०२ जून २०२२

नई दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में 'तुम्हारा नाम क्या है– तिब्बत' पुस्तक का विमोचन करते प्रो. समदोंग रिनपोछे और अन्य गणमान्य हस्तियां।

नई दिल्ली। वरिष्ठ भारतीय पत्रकार श्री चंद्रभूषण द्वारा हिन्दी में लिखित तिब्बत पर पहली जानकारीपरक पुस्तक 'तुम्हारा नाम क्या है-तिब्बत' का औपचारिक विमोचन नई दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में हुआ। ०१ जून २०२२ को आयोजित विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रो. समदोंग रिनपोछे (पूर्व कालोन ट्रिपा, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन) के

अलावा श्री रिनचेन खांडू खिरमे (राष्ट्रीय संयोजक, कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज– इंडिया), श्री राम चंद्र राही (अध्यक्ष, गांधी स्मृति संस्थान), श्री वेद प्रताप वैदिक (वरिष्ठ पत्रकार), प्रो हरीश खन्ना (पूर्व विधायक दिल्ली),श्री अशोक कुमार (सचिव, गांधी शांति प्रतिष्ठान) तथा अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस पुस्तक का अंग्रेजी में शाब्दिक अनुवाद 'तिब्बत- व्हाट इज योर नेम?' होगा।

श्री चंद्रभूषण ने अपनी पुस्तक का परिचय देते हुए चीनी कम्युनिस्ट सरकार की पांडुलिपियों और ब्लूप्रिंट को उद्धृत करते हुए रेखांकित किया कि चीन सरकार ने किस तरह से१९४९ से तिब्बत के पारिस्थितिकीय संसाधनों, सांस्कृतिक समावेश और तिब्बती पहचान को तबाह कर दिया है। उन्हों ने कहा कि नाते चीनी सरकार द्वारा २०१५ में आयोजित पत्रकारों के तिब्बत दौरे का हिस्सा होने के नाते उन्होंने ल्हासा, चेंगदू और तिब्बत के अन्य हिस्सों का दौरा किया। यह पुस्तक समकालीन चीनी इतिहास का एक रहस्योद्घाटन है। इस में तिब्बत की पहचान की कहानी, कम्युनिस्ट चीन की नई डिजाइन वाली नीतियों की विफलता, चीन के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास और इस मोर्चे पर भारत की मजबूरी के कारण हुई अपूरणीय क्षति का वर्णन किया गया है।

श्री चंद्रभूषण ने तिब्बत के भीतर उन तिब्बतियों की वास्तविकताओं और भावनाओं को कलमबद्ध किया है, जिन्होंने यातनाओं, कारावास और अधीनता के सभी कठोर प्रयासों के बावजूद तिब्बत की स्वतंत्रता की लौ को अटूट और अजेय बना रखा है। साथ ही परम पावन १४वें दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन में अपनी आस्था को बना रखा हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भंते रिनपोछे ने श्री चंद्रभूषण को तिब्बत पर उनकी पुस्तक के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। प्रो रिनपोछे ने बताया कि जब उन्हें पहली बार पुस्तक के बारे में अवगत कराया गया, तो उन्होंने सोचा था कि पुस्तक लेखक के यात्रा अनुभवों के बारे में है। लेकिन बाद में जब उन्हें पुस्तक पढ़ने का मौका मिलातो उन्हें पता चला कि पुस्तक केवल मात्र पुस्तक नहीं है। इसमें तिब्बत की संस्कृति और इतिहास, प्राचीन और आधुनिक पहलुओं को भी कवर किया गया है। यह शांतिरक्षित, पसंभव, दीपांकरशिरजन, राहुल संस्कृतायन, गेदुन चोफेल और तिब्बत से संबंधित कई अन्य व्यक्तित्वों और विषयों के बारे में बात करती है।

रिनपोछे ने स्वीकार किया कि वह पूरी किताब को पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ हिस्सों को पढ़ा और महसूस किया कि यह तिब्बत पर एक अच्छी किताब है। शाक्य पंडित के श्लोक का हवाला देते हुए कि 'जैसे बिना काना सेब खाए भीकोई रंग से उसका स्वाद बता सकता है। उसी तरह जब किसी के पास विश्लेषणात्मक बुद्धि होती हैतो दूसरों के अंतरतम विचारों को जाना जा सकता है'-रिनपोछे ने कहा कि पुस्तक के कुछ हिस्से के अच्छे अवलोकन से ही कोई अच्छी किताब जान सकता है। पुस्तक को महत्वपूर्ण बताते हुएउन्होंने श्रोताओं से तिब्बत के बारे में और जानने और समझने के लिए इस पुस्तक को पढ़ने का अनुरोध किया।

पुस्तक के शीर्षक 'तुम्हारा नाम क्या है-तिब्बत'के संबंध में रिनपोछे ने कहा किया कि तिब्बत के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या हैतो वह जवाब देंगे, 'मेरा नाम बोध है'। फिर इस शब्द के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हुए रिनपोछे ने कहा कि यह भारत से उत्पन्न एक संस्कृत शब्द है और प्राचीन काल में भारत के लोगों ने तिब्बत को बोध के रूप में संदर्भित किया था।

तिब्बत के भविष्य पर श्री वेद प्रताप वैदिक के सुझावों का स्वागत करते हुए रिनपोछे ने कहा कि परम पावन दलाई लामा ने पिछले तीन दशकों से तिब्बत मुद्दे के समाधान के लिए मध्यम मार्ग नीति की परिकल्पना की हुई है। इस दृष्टिकोण के तहतसभी तिब्बतियों के लिए वास्तविक स्वायत्तता के लिए चीन-तिब्बत वार्ता के ग्यारह दौर आयोजित किए गए थे। हालांकि, चीन की सतही मांगों के कारण २०११ में बातचीत बंद हो गई। चीन की पहली मांग यह स्वीकार करने की थी कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा है। उनकी दूसरी मांग यह थी कि वास्तविक स्वायत्तता में केवल तथाकथित तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र शामिल होंगे। इसमें तिब्बत के अन्य पारंपरिक प्रांतों, यानी डोटो और डोमी को शामिल नहीं किया गया था। यह तिब्बत के संदर्भ में पूरी तरह झूठ है और तिब्बत के लिए अस्वीकार्य है।

मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देते हुएरिनपोछे ने कहा कि अधिकांश लोग स्वायत्तता और स्वतंत्रता के बीच के अंतर को नहीं जानते हैं। उन्होंने इस अंतर पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वायत्तता स्वशासन की भाषा है और स्वतंत्रता राजनीति की भाषा है। रिनपोछे ने श्रोताओं से गांधीजी के 'स्वराज बनाम स्वतंत्रता' को पढ़ने के लिए कहा ताकि मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

अपने संबोधन के समापन में रिनपोछे ने कहा कि तिब्बत का मुद्दा न केवल एक या दो देशों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है। विश्व इतिहास के २०० वर्षों को युद्धों, विनाशों और प्रतिकूल घटनाओं का इतिहास बताते हुए उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए समझने और मानवता और दुनिया की भलाई के लिए काम करने का समय है।

विमोचन समारोह को श्री रामचंद्र राही, श्री वेद प्रताप वैदिक, प्रो हरीश खन्ना, श्री अशोक कुमार और श्री आर के खिरमे ने भी संबोधित किया।

तिब्बतियों, भारतीय समर्थकों और तिब्बत के मित्रों सहित लगभग सौ लोगों ने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लिया। इनमें तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि न्गोडुप डोंगचुंग और सचिव धोंडुप ग्यालपो, सम्यलिंग तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी दोरजी छेरिंग, फाउंडेशन फॉर नॉन वॉयलेंट अल्टरनेटिव के ट्रस्टी श्री ओ.पी. टंडन,वरिष्ठ भारतीय पत्रकार श्री विजय क्रांति, मजनुं का टिला और बुद्ध विहार से तिब्बती संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय, दिल्ली द्वारा श्री चंद्रभूषण और गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के सहयोग से किया गया।

• 'चीन पर कांग्रेस के कार्यकारी आयोग' ने तिब्बत मुद्दे को लेकर सुनवाई की

tibet.net, २४ जून २०२२

धर्मशाला। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा विधायी जनादेश से गठित 'चीन पर कांग्रेस-कार्यकारी आयोग' ने चीन में मानवाधिकारों की निगरानी और कानून के शासन के विकास को लेकर 'तिब्बत: एक अनसुलझे संघर्ष को सुलझाने में आ रही बाधाएं' विषय पर सुनवाई की। आयोग की सुनवाई का मकसद संवाद की बहाली में आनेवाली बाधाओं को दूर करना है। इस संवाद की बहाली से तिब्बती लोगों की मानव अधिकारों की आकांक्षाएं पूरी

चीन पर कांग्रेस के कार्यकारी आयोग द्वारा तिब्बत मुद्दे की सुनवाई।

हो सकती हैं और धर्म, संस्कृति और भाषा पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त हो सकती हैं। संवाद बहाली की यह कोशिश तिब्बत और चीनी कम्युनिस्ट शासन के बीच संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की परम पावन दलाई लामा की इच्छा को रेखांकित करती है। सुनवाई के दौरान तिब्बती इतिहास और अंतरराष्ट्रीय कानून के पहलुओं पर भी चर्चा की गई और इस बात पर भी चर्चाहुई कि अमेरिकी नीति कैसे इस लक्ष्य का समर्थन कर सकती है।

सीनेटर जेफ मर्कले और सीनेटर जिम मैकगवर्न की अध्यक्षता में चली सुनवाई के दौरान क्रेधा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर माइकल वैन वॉल्ट वैन प्राग, हांगकांग के सिटी यूनिवर्सिटी में सेवानिवृत्त चेयर प्रोफेसर मान-शियांग लाउ, पूर्व सीटीए अधिकारी और उत्तरी अमेरिका में परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि कालोन त्रिसुर तेनज़िन नामग्याल टेथोंग और अमेरिकन पर्पस में योगदान संपादक एलेन बोर्क अपनी गवाही दीं।

सीनेटर मर्कले की तिब्बत के अंदर चीन की प्रतिबंधात्मक और जोड़-तोड़ वाली नीतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी के बादसीनेटर जिम मैकगवर्न ने चीन-तिब्बत वार्ता को फिर से शुरू करने में अमेरिकी सरकार की रुचि व्यक्त करते हुए तिब्बत की स्थिति को प्रमुखता दिलाने में अमेरिकी कांग्रेस के योगदान और पहलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा,'अमेरिकी सरकार लगातार चीन से बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान करती रही है। लेकिन यह काम नहीं किया गया है। १२ साल से तिब्बती तैयार हैं, अमेरिका पूछ रहा हैलेकिन चीनियों ने मुंह मोड़ रहे हैं।

प्रोफेसर माइकल वैन वॉल्ट वैन प्राग ने अपने दस वर्षों के सहयोगात्मक शोध के निष्कर्षों के आधार पर अपनी गवाही प्रस्तुत की, जिसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तिब्बत को चीन के अभिन्न अंग के रूप में दी गई मान्यता को वापस लेने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि 'इस मान्यता की वजह से पीआरसी तिब्बतियोंके साथ बातचीत करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाता है, साथ ही यह तिब्बत के लाभ लेने के मुख्य स्रोत को कम कर देती है।' उन्होंने आगे कहा कि इसी मान्यता के कारण तिब्बत को लेकर अंतरराष्ट्रीय निगरानी और वहां अमानवीय दुर्व्यवहार के लिए बीजिंग को जिम्मेदार ठहराने की शक्ति को सीमित कर दिया है क्योंकि इस मान्यता के कारण ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय तिब्बत को चीन के आंतरिक मुद्दे के रूप में मानने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत 'हमारा शोध दृढ़ता से इस तथ्य को स्थापित करता है कि तिब्बत विभिन्न कालखंडों में मंगोल, मांचू और यहां तक कि ब्रिटिश अधिकार या प्रभाव में कम या ज्यादा रहा है, लेकिन इतना तय है कि यह कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था। हालांकि 'स्वतंत्र' शब्द का वही अर्थ नहीं रहा है जैसा कि आधुनिक कानूनी अर्थों में माना जाता है। और इसलिएपीआरसी तिब्बत को चीन के गणराज्य या पूर्व के साम्राज्यों के काल से 'विरासत में' प्राप्त नहीं कहसकता है, जैसा कि उसका दावा है। इसीलिए तिब्बत वास्तव में और कानूनी तौर पर भी१९१२ से १९५०/५१ तक एक स्वतंत्र देश था, जब तक कि पीआरसी ने इस पर आक्रमण नहीं किया था।'

प्रोफेसर माइकल वैन वॉल्ट ने अपनी गवाही में कहा कि, इसलिए 'चीन-तिब्बती संघर्ष को बातचीत से समाधान करने के लिए और तिब्बत में चीन की उपस्थिति और शासन की वैधता को खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।न कि ऐसे बयानों की,जो तिब्बत पर संप्रभुता के चीन के दावे को स्वीकार करते हैं। इसके लिए तिब्बत को एक अधिकृत देश कहने और इसी के अनुरूप इस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है।असल में तिब्बती विदेशी अधीनता और प्रभुत्व में जी रहे लोग हैं। वे न तो चीनके 'अल्पसंख्यक' समुदाय हैं न ही वहां के कोई 'जातीय समूह'। पीआरसी द्वारा उपयोग की जा रही इस तरह की शब्दावली को स्वीकार कर लेने से तिब्बती लोग अपनी उचित स्थिति से वंचित हो जाते हैं और परोक्ष रूप से आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। और अंत में, यह आवश्यक है कि तिब्बत मुद्दे को चीन-तिब्बत संघर्ष के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय विवाद माना जाए और इसी स्तर से इस समस्या का निराकरण किया जाए,जो पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिकी सरकार के दायरे और जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है, चीन के आंतरिक मामले के तहत। उन्होंने आगे राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा ताइवान और यूक्रेन के संदर्भ में बल प्रयोग द्वारा किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा करने के प्रयास को मान्यता नहीं देने की अमेरिकी नीति पारित किए जाने की भी याद दिलाई।

प्रोफेसर मान-शियांग लाउ ने अपनी गवाही में चीन के १९४९ से पहले के आधिकारिक ऐतिहासिक अभिलेखों में तिब्बत को संप्रभु के रूप में दर्शाए जाने का उल्लेख किया। अपनी गवाही के समर्थन में उन्होंने तिब्बत को एक गैर-चीनी विदेशी इकाई के रूप में चित्रित करने वाले मिंग और किंग राजवंशों के आधिकारिक मानचित्रों को भी प्रदर्शित किया।चीन ने राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र के संबंधित समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं,जिसका अर्थ है कि१९१९ के बाद से ही चीन ने सैन्य शक्ति के बल पर क्षेत्रों को हासिल नहीं करने का वादा किया है।साथ ही पीआरसी ने अन्य देशों को उनकी पिछली औपनिवेशिक विजय और चीन के साथ उनकी पिछली 'बदमाशी' की भी लगातार निंदा की है। यह कहते हुए प्रोफेसर लाउ ने कहा, 'पीआरसी को इस तथ्य को साबित करना होगा कि उसकी १९५० की तिब्बत विजय एक ऐसे क्षेत्र के 'एकीकरण' के रूप में है जो 'प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है।' अपनी गवाही में दो महत्वपूर्ण मौलिक अवधारणाओं- पहला 'चीनी इतिहास' का पीआरसी-संस्करण और दूसरा आधिकारिक चीनी अभिलेखों के आधार पर वास्तविक चीनी इतिहास के बीच व्यापक असमानताओं को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर लाउ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीआरसी का तिब्बत पर संप्रभुता का प्रमाण न केवल विकृतियों पर आधारित है बल्कि १९४९से पहले के चीनी अभिलेखों में पूर्ण रूप से जालसाजी करने पर आधारित है।

सुनवाई में तीसरे पैनलिस्ट तेनज़िन नामग्याल टेथोंग ने २०वीं शताब्दी में तिब्बत-चीन संबंधों पर संक्षेप में बात की, जिसमें तिब्बत मुद्दे के समाधान की दिशा में प्रयास भी शामिल थे। माओ के चीन पर कब्जे के बाद पीएलए के आक्रमण और बाद के अपनी स्वायत्तता की रक्षा में अंतरराष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र के समर्थन की मांग के तिब्बती सरकार के प्रयासों को याद दिलाते हुएउन्होंने कहा कि, 'चीन को सही पता था कि इस तरह के आक्रमण के लिए बयानबाजी का औचित्य पर्याप्त नहीं था, इसीलिए उसने तिब्बत को औपचारिक रूप से समझौते को अंतिम रूप देने को बातचीत के लिए बुलाया और अंततः १७ सूत्री समझौते को मूर्त रूप दिया। इसपर तिब्बती प्रतिनिधियों ने दबाव में हस्ताक्षर किए। तिब्बत अगले कुछ वर्षों के दौरान समझौते की व्यापक सीमा के भीतर काम करने का प्रयास करता रहा। लेकिन इसके बावजूद, चीन ने उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में काम नहीं किया जिनके बारे में परम पावन दलाई लामा को माओ से व्यक्तिगत आश्वासन प्राप्त हुआ था। इससे अंततः सर्वव्यापी असंतोष पैदा हुआ, जिसका समापन१० मार्च १९५९ के तिब्बती विद्रोह और चीनी दमन के रूप में हुआ।

समझौता

तेनज़िन नामग्याल तेथोंग ने आगे कहा कि इस घटना के कारण परम पावन और तिब्बतियों को तिब्बत से निर्वासित होना पड़ा, जबकि पीआरसी द्वारा

तिब्बत को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट दिया गया। उन्होंने जारी रखते हुए कहा कि,हालांकि१९७९की शुरुआत में चीन ने तिब्बती मुद्दे को इतना महत्वपूर्ण समझा कि उस पर दोबारा गौर किया जाए। देंग शियाओपिंग ने दलाई लामा के बड़े भाई को बीजिंग आमंत्रित किया और घोषणा की कि अलगाव के अलावाहर चीज पर चर्चा की जा सकती है। इस सफल बैठक ने परम पावन दलाई लामा और चीनी सरकार के बीच नए सिरे से संवाद का मार्ग प्रशस्त किया। दशकों के गतिरोध के बाद २००१में संवाद को फिर से बहाल किया गया था।तब तिब्बती प्रतिनिधियों ने २००८के तिब्बत-व्यापी विरोध के बाद भी २०१०में चीन की वार्ता प्रक्रिया की समाप्ति तक बैठकों में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना जारी रखा। इस घटनाक्रम पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि 'सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भीचीन तिब्बत में अपने शासन की वैधता को सही ठहराने की आवश्यकता पर ही जोर देता रहा है। और यह कि शायद अब उसे अपने शासन में कमियों का अहसास हो गया है, तभी चीन ने भी बार-बार परम पावन दलाई लामा के साथ सीधा संवाद शुरू करने की बात की है और इन बकाया मुद्दों के सार्थक समाधान खोजने की स्पष्ट आवश्यकता को प्रदर्शित किया है। इसलिए, उन्होंने अमेरिका और अन्य पक्षों से वार्ता के माध्यम से चीन-तिब्बत तनाव को सुलझाने के लिए निरंतर प्रयास और समर्थन का आग्रह किया।

एलेन बोर्क ने गवाही दी कि वस्तुतः तिब्बत मुद्दे पर अमेरिकियों के बहुत कम ध्यान के बावजूद, तिब्बत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। इस प्राथमिकता का समर्थन उन क्रियाकलापों से स्पष्ट हो जाता है जो पार्टी की निगरानी, दमन और नियंत्रण से लेकर महासचिव शी जिनपिंग के धर्म का चीनीकरण करने के लक्ष्य के अलावा तिब्बत केप्राकृतिक संसाधनों के दोहन और भारत-तिब्बत सीमा पर सैन्य बलों के जमावड़े में दिखाई देता है।

तिब्बत मुद्दे से निपटने के लिए अमेरिका के दृष्टिकोण में लगातार बदलाव को देखते हुए एलेन बोर्क ने चीनी और तिब्बती राजनीतिक कैदियों, असंतुष्टों, लोकतंत्र कार्यकर्ताओं, स्वतंत्र पत्रकारों और वकीलों के लिए नए सिरे से और दोगुना समर्थन जुटाने की सिफारिश की। उन्होंने चीनी साम्राज्यवादी शासन के अंत के बाद से अमेरिकी तिब्बत नीति की एक स्वतंत्र समीक्षा करने का भी सुझाव दिया, जिसमें राजनयिक इतिहास और आंतरिक विचार-विमर्श शामिल हैं।जिन्होंने तिब्बत के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है और चीन के हमले का मुकाबला करने में तिब्बत नीति को अंतरराष्ट्रीय कानून सहित लोकतांत्रिक मानदंडों पर अमेरिका के हित के अनुरूप खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि इससे अगले दलाई लामा के चयन के लिए तिब्बती प्रक्रिया की अखंडता पर सहयोगियों को एकजुटता के साथ शामिल करके हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

इसके अलावा, उन्होंने अमेरिका से सरकार के शीर्ष स्तर पर केंद्रीय तिब्बत प्रशासन (सीटीए) के निर्वाचित अधिकारियों का स्वागत करने और उन्हें लोकतंत्र और अन्य मंचों के शिखर सम्मेलनों में शामिल करने का आग्रह किया।साथ ही तिब्बत को अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विश्वविद्यालय परिसरों और राज्य और स्थानीय स्तर पर चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयासों का एक हिस्सा बनाए जाने का भी आग्रह किया।

पैनलिस्टों और उपस्थित लोगों के बीच एक घंटे के प्रश्न-उत्तर सत्र के बाद सुनवाई समाप्त हुई।

ई-गवर्नेंस के लिए सीटीए प्रतिनिधिमंडल का एस्टोनिया अध्ययन दौरा
tibet.net, १७ जून, २०२२

ई-गवर्नेंस के लिए एस्टोनिया मे सीटीए का प्रतिनिधिमंडल।

एस्टोनिया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के शासन तंत्र का डिजिटलीकरण करने के १६वें कशाग के विजन को मूर्तरुप देने के लिए १० सीटीए कर्मचारियों ने एस्टोनिया (यूरोप) का अध्ययन दौरा किया। यह दौरा ई-गवर्नेंस अकादमी (ईजीए) द्वारा आयोजित किया गया था। सीटीए कर्मचारियों की अगवानी ईजीए की कार्यक्रम निदेशक एनेला कीरात्स ने की।

पहले दिन की शुरुआत ईजीए के प्रबंधन बोर्ड की सदस्य अरवो ओटद्वारा स्वागत भाषण और एस्टोनिया के ई-गवर्नेंस के अवलोकन के साथ हुई। इसके बाद ईजीए के स्मार्ट गवर्नमेंस विशेषज्ञ प्रीत विकेल द्वारा सप्ताह की गतिविधि के विवरण के बारे में जानकारी दी गई। टीम को ईजीए की कार्यक्रम निदेशक एनेला किरात द्वारा ई-गवर्नेंस अकादमी की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी गई।

प्रतिनिधिमंडल ने एस्टोनिया की संसद का भी दौरा किया और एस्टोनियाई सांसद और एस्टोनिया में तिब्बत समर्थक समूह की अध्यक्ष योको अलेंडर और एस्टोनियाई सांसद एनेली एकरमैन से मुलाकात की। योको ने एस्टोनियाई ई-संसद की शुरुआत और शासन के प्रत्येक चरण में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने शासन के डिजिटलीकरण को लेकर टीम के सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का भी उत्तर दिया। बाद में, एस्टोनियाई संसद की सूचना प्रणाली के निदेशक कार्ल-मॉर्टन कोप्पेल ने एक स्लाइड प्रस्तुति दी कि कैसे एस्टोनियाई ई-संसद आयोजित करने का प्रबंधन किया जाता है, संसद के फैसले कैसे किए जाते हैं और संसद में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्ताव कैसे पारित किए जाते हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने एस्टोनियाई प्रधानमंत्री कार्यालय का भी दौरा किया और ई-कैबिनेटद्वारा कागज रहित काम को लेकर निर्णय लेने वाली पूरी प्रक्रिया को समझा।सरकारी कार्यालयों के संचार निदेशक कटेरिन पजुमागीने इस बात पर एक प्रस्तुति दी कि एस्टोनियाई प्रधानमंत्री ई-कैबिनेट बैठकें कैसे करते हैं और ई-कैबिनेट निर्णय इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे किए जाते हैं। उन्होंने पारंपरिक कैबिनेट बैठकों के डिजिटल आधारित कैबिनेट बैठकों में परिवर्तन के विभिन्न चरणों के बारे में भी बताया।

ई-गवर्नेंस अकादमी (ईजीए) एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन है जो एस्टोनिया सरकार, ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट (ओएसआई) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक संयुक्त पहल है। इसकी स्थापना वर्ष २००२में हुई थी। ईजीए सार्वजनिक क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों को डिजिटल परिवर्तन करने में सहायता करता है। ईजीए ई-सरकारी तकनीकी समाधानों के कार्यान्वयन में संगठन को परामर्श, प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, अनुसंधान और सहायता प्रदान करता है।

• लोकसभा के सांसद तपीर गाओ ने अरुणाचल प्रदेश में चोफेलिंग तिब्बती सेटलमेंट का दौरा किया

tibet.net, २३ जून २०२२

चोफेलिंग, मियाओ। भारतीय लोकसभा के माननीय सांसद श्री. तपीर गाओ ने गुरुवार को चोफेलिंग तिब्बती बस्ती का दौरा किया, जहां स्थानीय तिब्बती विधानसभा के अध्यक्ष रिनजिंग दोरजी, कार्यवाहक तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी तेनजिन रंगडोल और चोफेलिंग मियाओ के सहकारी समिति के निदेशक मंडल के अध्यक्ष ताशी धोंडुप समेत संबंधित शिविरों के नेताओं ने उनके आगमन का गर्मजोशी से स्वागत किया।

तिब्बती सेटलमेंट के दौरे पर भारतीय लोकसभा के सांसद श्री. तपीर गाओ।

एमपी गाओ ने कहा कि अल्प सूचना पर उनका दौरा सेटलमेंट को देखने के लोभ के कारण हुआ है, क्योंकि वह पहले यहां नहीं आए थे। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य और अरुणाचल (पूर्व) का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य होने के नाते वह अक्सर निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों से अनेक मौकों पर दिल्ली में मिलते रहते हैं। इसी प्रकार, तिब्बती संसद के कुछ सदस्यों के निमंत्रण पर उन्होंने तिब्बती निवासियों को किसी भी तरह की सहायता और सहयोग करने के लिए यहां की यात्रा की है।

उन्होंने निवासियों की शिकायतों के बारे में जानकारी हासिल की और उन्हें इन शिकायतों को संबंधित कार्यालयों में जमा करने के लिए कहा और विशेष रुप से निवासियों द्वारा प्रस्तावित सुपारी के पत्तों के डिस्पोजल यूनिट की स्थापना को लेकर उनके साथ संपर्क में रहने के लिए कहा। इन दिनों चलन में आए इन रीसाइकिल करने योग्य कप और प्लेट बनाने के लिए राज्य की ओर से न्यूनतम सहायता की जरुरत है।

इस बीच, सांसद गाओ ने इस सेटलमेंट की आत्मनिर्भरता की सराहना की। बस्ती के कालीन खंड में बुनी गई कालीन की एक छोटी सी स्मारिका देकर उनका अभिनंदन किया गया।

• मुझे बोलने के परिणाम का पछतावा नहीं है : एनेस कांटर फ्रीडम

tibet.net, ०१ जून २०२२

ब्रुसेल्स, ३१ मई २०२२।प्रतिनिधि रिगज़िन जेनखांग ने यूरोपीय संसद में एनबीए के पूर्व बास्केटबॉल स्टार एनेस कांटर फ्रीडम और उपाध्यक्ष पिकेर्नो से मुलाकात की। वह ब्रसेल्स में दो दिवसीय एडवोकेसी दौरे पर हैं और इस दौरान सांसदों, पत्रकारों और अन्य संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं।

प्रतिनिधि रिगज़िन जेनखांग, एनबीए के पूर्व स्टार एनेस कांटर फ्रीडम, ईपी के उपाध्यक्ष पिसीर्नो, यूएनपीओ के महासचिव, स्टाफ और विश्व उग्युर कांग्रेस के प्रतिनिधि।

चीन सहित अधिनायकवादी शासनों के खिलाफ बोलकर अपने एनबीए करियर का बलिदान करने वाले एनेस कांटर फ्रीडम ने अपने अनुभव को साझा किया कि कैसे वह मानवाधिकारों की रक्षा में शामिल हो गए और अपने देश तुर्की द्वारा लगाए गए इंटरपोल 'रेड नोटिस'के निशाने पर आ गए।

चर्चा के दौरान प्रतिनिधि जेनखांग ने 'मन को नियंत्रित करने'की चीन की नई नीति के बारे में बात की। इसे अगर समय रहते नहीं पलटा गया तो तिब्बती धर्म, पहचान और संस्कृति के पूर्ण उन्मूलन का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने श्रोताओं को यह भी बताया कि कैसे यूरोपीय और तिब्बती मूल के अन्य नागरिकों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ न बोलने के लिए मजबूर और बेअसर किया जाता है।

तिब्बती लोगों की ओर से प्रतिनिधि जेनखांग ने उन तिब्बतियों के लिए बोलने की अपनी प्रतिबद्धता और तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एनेस कांटर की अवज्ञा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। कृतज्ञता के प्रतीक के रुप में उन्होंने एनेस कांटर को एक पारंपरिक सफेद दुपट्टा भेंट किया और उन्हें परम पावन दलाई लामा और आर्कबिशप डेसमंड टूटू द्वारा लिखित 'बुक ऑफ जॉय' की एक प्रति भेंट की। पुस्तक ग्रहण करते समय उन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में परम पावन के साथ अपनी आभासी बातचीत को याद किया।

यूएनपीओ के महासचिव, विश्व उग्यूर कांग्रेस, बेल्जियम के प्रतिनिधि और स्टाफ सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे।

• प्रतिनिधि डॉ. आर्य ने टोक्यो में तियानमेन मेमोरियल कार्यक्रम में भाग लिया

tibet.net, ०५ जून २०२२

प्रतिनिधि डॉ. आर्य और वेन कोबायाशी शुई के साथ एक कार्यक्रम में।

टोक्यो। तियानमेन स्क्वायर नरसंहार घटना का स्मारक कार्यक्रम आज ०४ जून को यहां चीनी दूतावास के सामने विरोध मार्च और नारों के रूप में मनाया गया।इस अवसर पर बंक्योकू सामुदायिक केंद्र हॉल में एक वार्ता कार्यक्रम और टोक्यो में एक मोमबत्ती जुलूस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक, तियानमेन नरसंहार जिकेन प्रोटेस्ट कमेटी ने जापान और पूर्वी एशिया के लिए परम पावन दलाई लामा के संपर्क कार्यालय के प्रतिनिधि डॉ. आर्य त्सेवांग ग्यालपो को टोक्यो के कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया था।

वक्ताओं के पैनल में चीनी लोकतंत्र आंदोलन के अध्यक्ष ओउ ताई,चीनी-अमेरिकी स्तंभकार चेन पोकोंग,दक्षिण मंगोलिया के डाइचिन ओलहुंडऔर हांगकांग डेमोक्रेसी मूवमेंट के विलियम शामिल थे। अमेरिका के चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता और 'ह्यूमेनिटेरियन चाइना' नामक संस्था के अध्यक्ष झोउ फेंगसो ने कार्यक्रम में ऑनलाइन भाग लिया। समिति के अध्यक्ष कोजिमा ताकायुकी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

दर्शकों को तियानमेन नरसंहार और चीनी सेना की बर्बरता की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई। समिति के सदस्यों ने चीनी और जापानी भाषाओं में २०१०में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लियू शियाओबो की तियानमेन नरसंहार पर लिखी

कविता पढ़ी। वक्ताओं ने बताया कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट नेतृत्व ने युवा चीन की आवाज का बेरहमी से गला घोंट दिया और प्रदर्शनकारियों की जान ले ली। उन्होंने चीनी नेतृत्व से वास्तविकता का सामना करने और लोकतंत्र और कानून के शासन को अपनाकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा बनने का आग्रह किया।

प्रतिनिधि आर्य ने उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित करने और तियानमेन नरसंहार पर तिब्बती विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए समिति को धन्यवाद दिया। उन्होंने चीन में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की निरंतर लड़ाई में चीनी भाइयों और बहनों के साथ तिब्बती लोगों की एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यद्यपि चीनी कम्युनिस्ट नेतृत्व ने ३३ साल पहले लोकतंत्र और युवा चीन की आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज न केवल लाखों चीनियों के दिल में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लाखों लोगों दिल और दिमाग में भी जिंदा और जीवंत है।

प्रतिनिधि आर्य ने चीनी अत्याचारों, मानवाधिकारों के उल्लंघन, धार्मिक स्वतंत्रता के दमन और तिब्बतियों द्वारा तिब्बत में आत्मदाह किए जाने के बारे में बात की। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट नेतृत्व के इस आरोप का खंडन किया कि तिब्बती अलगाववादी और चीन विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि लारुंग-गर और याचेन-गर मठों का विनाश, तिब्बतियों और चीनी भक्तों का जबरन अलगाव और तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता पर तिब्बतियों के ज्ञापन का चीनी जनता के सामने खुलासा न करना इस तथ्य का संकेत है कि चीनी कम्युनिस्ट नेतृत्व असली अलगाववादी है, तिब्बती नहीं।

हॉल पूरी तरह से जापानी, चीनी, दक्षिण मंगोलियाई और हांगकांग के बुद्धिजीवियों और समर्थकों से भरा हुआ था। तिब्बत के लिए जापानी संघ के एक गैर-पक्षपाती एसोसिएशन 'सुपर संघ'के भंते हयाशी शुई और भंते कोबायाशी शुई ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

वार्ता कार्यक्रम चीनी लोगों द्वारा मातृभूमि में लोकतंत्र की मांग के लिए संघर्ष के साथ समर्थन और एकजुटता व्यक्त करने वाले एक प्रस्ताव पारित करने के साथ समाप्त हुआ। प्रस्ताव में चीनी नेतृत्व से अपने लोगों के खिलाफ दमन और अत्याचार बंद करने का आग्रह किया गया है।

इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आयोजकों और वक्ताओं ने मीडिया से बातचीत की। हॉल के प्रवेश द्वार पर विरोध की क्रूरता और दमन को प्रदर्शित करने वाली तस्वीरें प्रदर्शित की गई थीं।

• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का५०वां सत्र: ४७सदस्य देशतिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर 'गंभीर रूप से चिंतित'

tibet.net, १६ जून २०२२

जिनेवा।संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ५०वें सत्र के दूसरे दिन संयुक्त राष्ट्र के ४७ सदस्य देशों ने कहा कि तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में वे 'गंभीर रूप से चिंतित' हैं।

१४ जून को उच्चायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट पर एक संवादात्मक चर्चा के दौरान क्रॉस रीजनल संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए नीदरलैंड ने ४७ सदस्य देशों की ओर से एक बयान दिया। बयान में चीन द्वारा विशेष रूप से तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान और हांगकांग में मानवाधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया।

बयान में कहा गया कि ये देश 'हांगकांग में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान में गिरावट और तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं।'

संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की हालिया चीन यात्रा और २८ मई के मिशन वक्तव्य के अंत के मद्देनजर, सदस्य देशों ने उच्चायुक्त पर विस्तृत रिपोर्ट का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसमें सिविल सोसायटी के लोगों की यात्रा और पहुंच पर लगाए गए बीजिंग प्रतिबंध शामिल हों।

इसके अलावा, इन देशों ने चीन से लोगों को देश में सार्थक और निरापद आवागमन की सुविधा प्रदान करने,कानून के शासन का पूर्ण रूप से पालन करने, मानवाधिकारों की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दायित्वों का पालन करने और नागरिक और अंतरराष्ट्रीय संधियों की राजनीतिक अधिकारों की पुष्टि करने का आह्वान किया।

चीन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर नीदरलैंड के नेतृत्व वाले संयुक्त बयान पर अल्बानिया, अंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बेलीज, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, इस्वातिनी, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्वाटेमाला, होंडुरास, आइसलैंड, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, लातविया, लिकटेंस्टीन, लाइबेरिया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, मार्शल द्वीप, मोनाको, मोंटेनेग्रो, न्यूजीलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पलाऊ, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सैन मैरिनो, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड औरसंयुक्त राज्य अमेरिका ने हस्ताक्षर किए।

१३मई को बुलाई गई ५०वीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नियमित सत्र ०८जुलाई को समाप्त होगा। ५०वें यूएनएचआरसी सत्र से पहले ४० से अधिक संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के एक समूह ने चीन से 'बर्बर और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघन' को रोकने का आह्वान किया और चीन तक 'बिना किसी बाधा के आवागमन' सुनिश्चित करने की मांग की।

• प्रतिनिधि डॉ. आर्य ने जापानी संसद के सम्मेलन कक्ष में प्रेस बैठक में भाग लिया

tibet.net, १६ जून २०२२

टोक्यो। जापानी संसद सत्र के समापन के दिन आज १६ जून को निचले सदन के सम्मेलन कक्ष में एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कांफ्रेंस में चीन द्वारा कब्जा कर लिये गए देशों के नागरिकों के प्रतिनिधियों ने जापानी सांसदों से अपनी समस्याओं के बारे में बात की। 'फ्री इंडो-पैसिफिक एलायंस' ने प्रेस कांफ्रेंस का समन्वय किया था। तिब्बत के लिए जापान संसदीय समर्थक समूह के पूर्व महासचिव नागाओ ताकाशी और लेखक- निबंधकार मिउरा कोटारो ने सम्मेलन की अध्यक्षता की।

जापानी संसद के निचले सदन शुगीन ने पिछली फरवरी में बिल पारित किया जिसमें चीन की आलोचना की गई और कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने

और पड़ोसी देशों में क्षेत्रीय आक्रमण के लिए उसकी निंदा की गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि उच्च सदन (सांगीन) भी इस सत्र के दौरान विधेयक को पारित कर देगा। लेकिन उच्च सदन द्वारा विधेयक को पारित न करने और इस मुद्दे पर सांसदों से अपील करने में उसकी विफलता के मद्देनजर प्रेस कांफ्रेंस बुलाई गई थी।

प्रतिनिधि डॉ छेवांग ग्यालपो आर्य ने कहा कि निचले सदन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन की निंदा करने वाले पिछले प्रस्ताव को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से स्वीकार किया था। इससे दमनकारी कम्युनिस्ट शासन से पीड़ित लोगों को बहुत आशा बंधी थी। इसके अलावा, इसने चीनी नेतृत्व को सही संदेश दिया है कि दुनिया देख रही है। हालांकि, उन्होंने खेद व्यक्त किया कि विधेयक उच्च सदन में पारित नहीं हो पाया।

प्रतिनिधि आर्य ने कहा कि सीसीपी नेतृत्व युद्ध और अस्थिरता का खतरा और कारण बन गया है। जापान एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है। यह एशिया और दुनिया में शांति और स्थिरता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है। इसे जिम्मेदारी और नेतृत्व ग्रहण करना चाहिए और मानवाधिकारों के उल्लंघन और अन्याय से पीड़ित लोगों के लिए बोलना चाहिए।

उग्यूर के गुलिस्तान एज़, दक्षिण मंगोलिया कुरिलताई के डॉ गोवरुद अर्चा, वर्ल्ड मंगोलियाई फेडरेशन के दारहाद हस्चुलु और स्टॉप मेडिका नरसंहार के नेमोतो युकिओ ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया और उच्च सदन में बिल को पारित होने पर अपना दुख और निराशा प्रकट की। .

प्रतिनिधियों ने प्रेस को गंभीर स्थिति के वापस आने के बारे में अवगत कराया और डाइट (जापानी संसद) के सदस्यों से स्वतंत्रता और न्याय के लिए अपने संघर्ष का समर्थन करने का अनुरोध किया। उग्यूर प्रतिनिधि ने आंसुओं के बीच अपनी मातृभूमि में अत्याचार और बर्बरता की घटनाएं सुनाईं।

• दलाई लामा राष्ट्र के रूप में तिब्बत के अंतिम प्रतीक हैं

theweek.in / न्गोडुप डोंगचुंग, २८ जून, २०२२, दलाई लामा | रॉयटर्स

बैठक को संबोधित करते हुए प्रतिनिधि डॉ. आर्य।

दुनिया जब ०६ जुलाई को परम पावन दलाई लामा का ८७वां जन्मदिन मना रही है, यह मेरे लिए खट्टा-मीठा का मिश्रित क्षण है। एक तरफ, मैं बहुत धन्य महसूस करता हूं कि मुझे दलाई लामा और तिब्बती प्रशासन के विभिन्न पदों पर ४५ वर्षों तक सेवा करने का अवसर मिला है, जिसमें कुछ अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल हैं। दूसरी ओर, जैसा कि वे कहते हैं, सभी अच्छी चीजों का अंत होना निश्चित है। इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तिब्बती नौकरशाहों की युवा पीढ़ी को मशाल सौंप दूं।

कहने की जरूरत नहीं है कि दलाई लामा आज एक विश्व-प्रसिद्ध आध्यात्मिक और नैतिक नेता हैं, जो भारत के सम्मानित अतिथि के रूप में ६३ वर्षों से अधिक समय से धर्मशाला में निवास कर रहे हैं। धर्मशाला कभी एक सुदूर और उजाड़ पहाड़ी शहर हुआ करता था।लेकिन अब यह अपने आप में एक विशाल शहर है, जहां दिल्ली से पांच, कभी-कभी छह सीधीदैनिक उड़ानें हैं। धर्मशाला आज एक तरह से दुनिया भर के बौद्धों के लिए आध्यात्मिक राजधानी और जीवन और आध्यात्मिकता में अर्थ तलाशने वालों के लिए एक बड़ा केंद्र बन गया है।

तिब्बतियों के साथ-साथ हिमालयी बौद्ध पट्टी और इससे अलग रहने वाले लोगों के लिए दलाई लामा सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अवलोकितेश्वर या चेनरेज़िग, करुणा के बोधिसत्व- तिब्बत के संरक्षक संत की तरह हैं। दलाई लामा १६४२ सेतिब्बत के आध्यात्मिक और इहलौकिक शासक रहे हैं। दलाई लामा तिब्बत राष्ट्र, इसमें बसने वाले लोगों और इसकी विशिष्ट ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के सर्वोच्च प्रतीक हैं।

हालांकि, परम पावन ने तिब्बत की धार्मिक शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित करने के माध्यम से आधुनिकीकरण करने का लगातार प्रयास किया है। आम तिब्बती बोलचाल में हमारे जीवंत लोकतंत्र को अक्सर परम पावन के उपहार' के रूप में पहचाना जाता है। २०११ में दलाई लामा द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के पूर्ण हस्तांतरण के बाद तिब्बती प्रशासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था आज एक निर्वाचित नेतृत्व के हाथों में है, जिसमें अधिकारियों, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों में स्पष्ट नियंत्रण, विभाजन और संतुलन है।

मानवीय मूल्यों और अंतर-धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने और वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी के अलावा परम पावन को दुनिया भर में शांति और अहिंसा के अग्रदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। परम पावन अक्सर कहते हैं कि २१वीं सदी संवाद की सदी होनी चाहिए और उन्होंने सच्चे, स्थायी मेल-मिलाप और सभी वैश्विक संघर्षों को हल करने के एकमात्र साधन के रूप में अहिंसा और संवाद की अथक वकालत की है। तिब्बत को मुक्त कराने के संघर्ष में हिंसा के उपयोग का लगातार विरोध करने और अपने लोगों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सहिष्णुता और आपसी सम्मान के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करने के लिए परम पावन को १९८९ में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

परम पावन के सबसे स्थायी वैश्विक योगदानों में से एक उनका प्राचीन भारतीय अहिंसा और करुणा के ज्ञान का पुनरुद्धार है। वे दिन गए, जब कुछ लोगों ने मिलावटी या विदेशी 'लामावाद' कहकर तिब्बती बौद्ध धर्म को ठुकरा दिया था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ उनके वर्षों के व्यापक विमर्श ने बौद्ध विज्ञान और दर्शन और बौद्ध धार्मिक साधना के बीच गहरी समझ विकसित की है और स्पष्ट सीमांकन किया है। प्राचीन भारतीय नालंदा परंपरा पर आधारित मन की जटिल कार्यप्रणाली से संबंधित बौद्ध विज्ञान और दर्शन पहले से ही विभिन्न विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाया और शोध किया जाने वाला धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक विषय बन गया है।

परम पावन अक्सर एक प्रार्थना को दोहराते हुए कहते हैं, 'जब तक यह अंतरिक्ष है और जब तक प्राणियों का अस्तित्व हैं, तब तक मैं भी संसार के दुखों को दूर करने में मदद करने के लिए बना रहूँ।' मैं यहां एक प्रार्थना के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं-'जिस तरह इस जीवन में मुझे दलाई लामा की सेवा करने का अवसर मिला है, मेरी कर्मों की निधि इतनी संचित और स्वस्थ हो कि मैं अगले जीवन में भी फिर से उनकी सेवा कर सकूं।'

लेखक नई दिल्ली में दलाई लामा के प्रतिनिधि हैं।

इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और इसका मतलब 'द वीक' के विचारों को प्रतिबिंबित करना नहीं है।

• शोक संदेश : डीआईआईआर ने श्री थुबटेन सम्फेल के निधन पर शोक व्यक्त किया

स्टाफ रिपोर्टर / ०४ जून, २०२२

धर्मशाला। एक अनुभवी राजनयिक, नौकरशाह और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के लोक सेवक थुबटेन सम्फेल का आज ०४ जून की सुबह अचानक निधन हो गया।

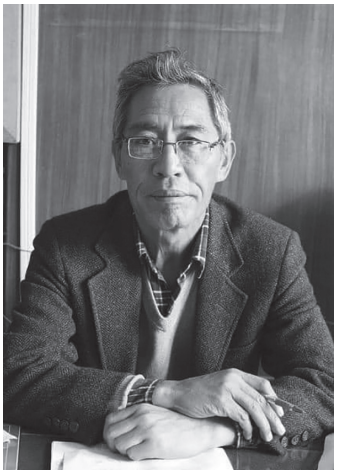

श्री थुबटेन सम्फेल

सम्फेल सीटीए के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग (डीआईआईआर) के पूर्व सचिव थे। उन्होंने पिछली बार तिब्बत नीति संस्थान के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया था।

लगभग चालीस वर्षों तक सीटीए की सेवा करने वाले सादा जीवन जीने वाले लेकिन सबसे बौद्धिक लोक सेवकों में से एक के निधन पर डीआईआईआर गहरा दुख व्यक्त करता है। कुंगो सम्फेल के अप्रत्याशित निधन पर सभी लोग शोकाकुल हैं और भविष्य में उन्हें प्यार और प्रशंसा के साथ याद करेंगे।

अपनी बौद्धिक और अकादमिक रुचि के लिए जाने जाने वाले कुंगो सम्फेल ने कई किताबें लिखी थीं, जिनमें 'फॉलिंग थ्रू द रूफ', 'द दलाई लामास ऑफ तिब्बत' (सह-लेखक) और 'कॉपर माउंटेन' शामिल हैं। उन्होंने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी तिब्बत पर व्यापक रूप से लिखा था।

डीआईआईआर के कालोन नोरजिंग डोल्मा ने अपने शोक संदेश में कहा, 'कुंगो थुप्टेन सम्फेल ला की लंबी विरासत को उनकी समर्पित सेवा, प्रेरक व्यक्तित्व और विभिन्न विभागों के माध्यम से तिब्बती मुद्दे में और विशेष रूप से डीआईआईआर में महत योगदान के लिए उनको सम्मान के साथ याद करते हैं। हम दुख और शोक की इस घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक प्रार्थना और संवेदना व्यक्त करते हैं।'

थुबटेन सम्फेल का संक्षिप्त विवरण

थुबटेन सम्फेल का जन्म १९५६ में ल्हासा में एक शालीन परिवार में हुआ था, जिन्होंने याब्शे ताकत्से परिवार के लिए काम किया था। छह साल की उम्र में वह अपने बड़े भाई के साथ तिब्बत से भागकर भारत आ गये। उनके आगमन के बाद उन्हें तिब्बती शरणार्थी नर्सरी स्कूल (वर्तमान में टीसीवी) में भर्ती कराया गया और बाद में कलिम्पोंग में डॉ ग्राहम के घर भेज दिया गया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में बीए और एमए की पढ़ाई की। एमए की पढ़ाई के दौरान सम्फेल ने एक वर्ष के लिए परम पावन दलाई लामा के कार्यालय में सचिव तेनज़िन गेचे टेथोंग के अधीन एक प्रशिक्षु के रूप में काम किया।

१९८० में वे सीटीए में शामिल हुए और १९८२ में उन्हें उप सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया। जुलाई १९८५ में कुंगो सम्फेल को वोसर ग्यालत्सेन कुंडलिंग के नेतृत्व में चौथे तथ्य-खोज प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में चुना गया था। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर-पूर्वी तिब्बत और चीन का दौरा किया। इस दौरान उन्हें प्रतिनिधिमंडल के आधिकारिक फोटोग्राफर के रूप में नामित किया गया था।

१९८८ में वे अमेरिका जाकर अध्ययन करने वाले तिब्बती फुलब्राइट विद्वानों के पहले समूह में थे और कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में पत्रकारिता का अध्ययन किया। इस अवधि में उन्होंने एक महीने के लिए अमेरिकी सांसद चार्ली रोज़ के कार्यालय में भी इंटर्नशिप की। इस तरह अमेरिकी संसद (कांग्रेस) में प्रशिक्षु के रूप में काम करने वाले संभवत: वह पहले तिब्बती थे।

अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थुबटेन सम्फेल ने सीटीए में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं जारी रखी। उन्होंने १९९१ में तिब्बत कार्यालय, न्यूयॉर्क में संक्षिप्त रूप से काम किया और १९९२ में वे काठमांडू स्थित तिब्बती शरणार्थी कल्याण कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में भेजे गये। वे १९९५ में स्थानांतरित होकर डीआईआईआर में वापस आ गये। उन्होंने कई वर्षों तक डीआईआईआर में तिब्बती बुलेटिन के संपादक के रूप में कार्य किया और १९९१ में उन्हें सूचना सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने इस पद के साथ-साथ २०१२ तक सीटीए के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्य किया।

२०१२ में उन्हें सीटीए के थिंक टैंक के तौर पर नव-स्थापित तिब्बत नीति संस्थान के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सीटीए में ३८ से अधिक वर्षों तक सेवा करने के बाद वह ०२ नवंबर २०१८ को सेवानिवृत्त हुए।

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Tenzin Jordan
Deputy Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

तेनजिंग जॉर्डन
उप–समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोनः 011–29830578
ई–मेलः indiatibet7@gmail.com

तुम्हारा नाम क्या है – तिब्बत' पुस्तक का विमोचन प्रो. समधोंग रिनपोछे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया।

तिब्बत पर कथाएं: परिवर्तन की आवश्यकता' विषय पर एक पैनल चर्चा में कनाडा के सांसद आरिफ विरानी, प्रो. हो-शियांग लाउ, प्रो. माइकल वैन वॉल्ट पराग, भारत के सांसद डॉ. शशि थरूर, और कलोन नोरज़िन डोल्मा।